

>

Title: Resolution regarding construction of canals through Ken-Betwa River Linking Project to overcome the problem of water scarcity and stray cows in the Bundelkhand Region.(Discussion-not concluded)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, before I call Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel to move his Private Member's Resolution regarding construction of canals through Ken-Betwa river linking project to overcome the problem of water scarcity and stray cows in the Bundelkhand region, the time for discussion on the Resolution has to be allotted by the House.

If the House agrees, two hours may be allotted for the discussion on the Resolution.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: So, the House is agreeing. We can now take up the Private Member's Resolution.

Now, Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“यह सभा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और पशुओं के चारे की अनुपलब्धता के कारण, क्षेत्र के लोग अपनी गायों को खुले में चरने के लिए छोड़ने पर

विवश हैं, जो आम तौर पर 'अन्न प्रथा' के नाम से जानी जाती है, और जो खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, सरकार से क्षेत्र में जल संकट की समस्या और अन्न प्रथा की परम्परा को दूर करने के लिए बांधों और तालाबों के अंतर्संयोजना तथा पुनर्भरण करने के लिए प्रस्तावित केन-बेतवा नदी सम्पर्क परियोजना से नहरों का संजाल निर्मित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह करती है।”

सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 17वीं लोक सभा के इस सत्र में, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे क्षेत्र की समस्या की आवाज़ उठाने के लिए, आज यह संकल्प, इस 17वीं लोक सभा का पहला संकल्प हमारे सदन में स्वीकृत हुआ है। सर्वप्रथम, मैं देशवासियों का आभार प्रकट करता हूँ कि पिछले पांच वर्षों में देश की सरकार ने, आदरणीय प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो क्रांतिकारी परिवर्तन, देश का जो गौरव बढ़ाने का काम किया, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के दर्शन कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का जो काम किया, उसके परिणामस्वरूप पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत के साथ इस बार देश में सरकार बनी है। सन् 2019 के आम चुनावों में देश में जो सरकार बनी है, यह सरकार देशवासियों ने जितनी ताकत के साथ बनाई है, जितने भरोसे के साथ बनाई है, उससे उनके मन में बहुत उम्मीदें हैं। पूरा देश जानता है, इसको एक-एक व्यक्ति जानता है।

मैं देशवासियों का आभार प्रकट करता हूँ और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, बुंदेलखंड हमारे देश का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। वहां बहुत कमियां हैं, किसानों के लिए पानी नहीं है। वहां नौजवानों के पास अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हैं। मैं उनकी बात आज यहां सदन में रखने के पहले, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे दूसरी बार सदन में उन्होंने अपनी आवाज़ रखने के लिए यहां पर भेजा है। मैं समझता हूँ कि उन्हीं की शुभकामनाएं हैं कि उनकी शुभकामनाओं के आधार पर आज पहला संकल्प मेरा यहां पर आया है, जिसके लिए मैं आज आपके समक्ष अपनी बात रखने जा रहा हूँ। यह सभा इस तथ्य को ध्यान में रखते

हुए कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और पशुओं के चारे की अनुपलब्धता के कारण क्षेत्र के लोग अपनी गायों को खुले में चरने के लिए छोड़ने पर विवश हैं। जो आम तौर पर 'अन्न प्रथा' के नाम से जानी जाती हैं। जो खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। सरकार बहुत तेज़ी से उस दिशा में काम कर रही है। जब से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो भाग है, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, गौशालाओं के लिए बहुत व्यापक तरीके से काम चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट है, वह संकट यह है कि वहां पर पानी की कमी है। किसानों के पास चारे की उपलब्धता नहीं है। किसान खाद्यान्न नहीं पैदा कर पा रहे हैं। उनके बच्चे पलायन को मजबूर हैं। हमारे यहां इन सभी कारणों को देखते हुए बड़ी भारी संख्या में वहां से पलायन हुआ है और लोग बाहर गए हैं।

केन-बेतवा नदी जोड़ने की बात है, लेकिन मैंने अपनी बात शुरू की है अन्न प्रथा से, छुट्टा गोवंश से। उसका कारण यह है कि बड़ी उम्मीद लगाए किसान बैठा रहता है कि बुंदेलखंड में कभी एक दिन पानी आएगा। लोगों के पास बहुत जमीने हैं, पर्याप्त मात्रा में वहां पर बहुत उपजाऊ भूमि है। उस पर अगर पानी की उपलब्धता हो जाएगी, तो निश्चित रूप से वहां पर इतनी अधिक पैदावार होगी। जैसे सदियों से वहां पर बड़ी ताकत के साथ किसानों ने काम किया और बहुत बड़ी भारी संख्या में वहां पर गाय हैं और दूध देने वाले पशु और मवेशी हैं, जिनको आधार बना कर वहां पर वर्षों से लोग इस पठारी क्षेत्र में भी बड़ी ताकत के साथ वहां पर काम करते रहे और किसान अपने पैरों पर खड़े रहे।

इस बात को मैं बड़े दर्द के साथ इस सदन में रख रहा हूँ कि आजादी के बहुत दिनों बाद तक वहां के जो प्रतिभाशाली लोग होते थे, अपनी शिक्षा के आधार पर, अपनी प्रतिभा और मेधा के आधार पर वे वहां से बाहर जाते थे। देश के और दुनिया के कोने-कोने में जा कर काम करते थे। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख होता है, जब मैं किसी भी महानगर में पहुंचता हूँ, खास तौर से अपना जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहां पर हमारे यहां से बहुत से लोग, पढ़े-लिखे लोग तो आते ही हैं, बहुत से श्रमिक, मज़दूर, यहां पर आ कर 20-30 मंजिलों की

बिल्डिंगों में ईटों और बालू उठाने का काम करते हैं। बड़ी तकलीफ होती है कि मेरे क्षेत्र के लोग यहां पर केवल अपने भरण-पोषण के लिए आते हैं।

इन सभी समस्याओं का समाधान है कि बुंदेलखंड को पानी मिल जाए। अगर बुंदेलखंड को पूरा पानी मिल गया तो आप तय मानिए कि बुंदेलखंड में इतनी क्षमता है, इतनी उर्वरक क्षमता है कि उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पहले परम्परागत ज्ञान के आधार पर हमारे पूर्वजों ने, चंदेल राजाओं ने बुंदेलखंड में 8 हजार तालाबों का निर्माण करवाया था। पूरा देश जानता है कि 8 हजार तालाब, छोटे-मोटे तालाब ही नहीं, हजारों हेक्टेयर्स के तालाब को जिस प्रकार से बनाया, जैसा जल प्रबंधन हुआ, उस पर बाहर की यूनिवर्सिटीज के लोग आकर आज रिसर्च कर रहे हैं। जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, वह निश्चित रूप से काबिले-तारीफ था। लेकिन पिछले 30-40 सालों में वहाँ पर ऐसी कोई बड़ी वाटर बॉडीज नहीं बनी। जो सतही जल है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रयास नहीं किए गए या दिल से प्रयास नहीं किए गए। आज जो भी बांध या नहरें बनी हैं, उससे किसानों को पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है और अनेकों प्रकार की दिक्कतें बढ़ रही हैं।

आज से हजारों वर्ष पहले 8वीं, 9वीं और 11वीं शताब्दी तक पठारी क्षेत्र में ऐसे बड़े-बड़े तालाब बनाए गए, जो आज भी वहाँ पर हैं। उनको देखने के लिए लोग आते हैं। आज भी मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी ताकत के साथ, जितनी क्षमता के साथ उन तालाबों में पानी होता था, देश आज़ाद होने के बाद अभी तक वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाया है। यह केन-बेतवा नदी जोड़ी जो योजना है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुई थी। इसके पहले भी नदी जोड़ने की बात हुई। अंग्रेजों के जमाने में, उन लोगों ने यातायात के साधन के लिए नदी जोड़ने का विचार रखा था कि हम यातायात के लिए नदियों को जोड़ेंगे तो हमें देश की धन-सम्पदा, यहाँ के पूरे मिनरल्स को बाहर ले जाने में सुविधा होगी। लेकिन जब देखा कि इसमें खर्च ज़्यादा आएगा तो उस खर्च को समझते हुए उन लोगों ने उसके बाद रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बनाया और नदियों के जोड़ने के काम को रोक दिया क्योंकि इस पर लागत ज़्यादा है। उन्होंने रेलवे लाइन का नेटवर्क बिछाया, जो आज यातायात का

बड़ा साधन है । आज हमारे देश की नदियों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे यहाँ जो केन नदी है, केन नदी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की जो बात होती है, देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो नदियों को जोड़ने वाला होगा । मैं अपनी सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, हमारी पूर्व में स्व. अटल बिहारी वापजेयी की जो सरकार थी, उसने केन-बेतवा को बड़ी संजीदगी के साथ लिया था । पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन था कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के पास जब तक सुविधा नहीं पहुँचे तब तक राजनीतिक का कोई मतलब नहीं है । उसी श्रृंखला में वहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने सोचा और हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा पानी के संकट से जूझ रहे क्षेत्र को केन और बेतवा को देने की बात की । आज केन और बेतवा की जो बात हो रही है, केन नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी है और बारिश के समय में पहाड़ी नदी टाइप का उसका स्वरूप है, जब बारिश के समय में पानी आता है तो पूरा पानी फ्लड के साथ बहुत तेजी के साथ बहता हुआ यमुना में मिल जाता है । वह पानी उपयोग में नहीं आता है और पूरा पानी व्यर्थ चला जाता है । केन को बेतवा से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड को मध्य प्रदेश के छत्तरपुर, टीकमगढ़ और मेरे संसदीय क्षेत्र के महोबा जनपद के बगल से होते हुए वहाँ से निकलते हुए झांसी जनपद में जाती है और झांसी जनपद में जाकर के बेतवा में मिलती है । हमारे इंजीनियर्स ने और जितने हमारे पर्यावरणविदों ने उस पर अध्ययन करके यह जो बनाया है, वह निश्चित रूप से काबिले-तारीफ है इसमें कोई दो राय नहीं है । अनेकों प्रकार की बातें हम लोगों के संज्ञान में हमेशा रहती हैं । पानी की उपलब्धता हो जाने के कारण से अगर प्रति व्यक्ति वहाँ पर जमीन का देखा जाए कि कितने लोगों के पास जमीन है तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में कुछ एक दो क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं, जहाँ पर अनुपजाऊ क्षेत्र हो, जहाँ पर जमीनें लोगों के पास ज़्यादा हों, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में किसानों के पास उपजाऊ भूमि देश के औसत से ज़्यादा है । केवल पानी नहीं है, इस पानी के कारण से जो वहाँ पर अच्छी नस्ल की देशी गायें होती थीं, जो दूध के लिए, खेती करने के लिए जिन-जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी, वह करते थे । जब अच्छा गोवंश वहाँ पर था तो उस गोवंश के आधार पर, उससे जैविक खेती भी लोग करते थे और अपने खर्चों में कटौती करके अच्छा उत्पादन करते थे ।

लेकिन पानी की अनुपलब्धता के कारण से, पानी की कमी के कारण से आज यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहाँ पर उनके पास सब संसाधन हैं, लेकिन पानी न होने के कारण से वह हमारी जमीन पूरी खाली पड़ी हुई है। मैं वहाँ के तालाबों की फोटो अगर पूरे सदन के सामने रखूँ, मैंने पिछली 16वीं लोक सभा में बहुत माननीय सदस्यों को वहाँ के तालाबों की फोटो लाकर उसका पूरा बंच बनाकर दिया था। पिछली बार जब कभी भी मैं बुंदेलखंड की बात रखने के लिए खड़ा होता था, सभी लोग समर्थन करते थे और बुंदेलखंड के लिए हमको एसोसिएट करते थे। उसके कारण से बुंदेलखंड की आवाज़ बड़ी दूर तक गई।

पिछली सरकार में हमारे यहाँ पेयजल का संकट हुआ। जानवरों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता था। मनुष्य तो कहीं न कहीं संसाधन उपलब्ध कर लेता है या संवेदनशीलता के कारण कोई न कोई उसे पीने का पानी मुहैया करा देता है। जो मूक पशु, मवेशी है, गाय, बैल हैं या यहाँ तक कहें कि जो जंगली जानवर हैं, उन्हें पीने का पानी नहीं मिलता है और वे पूरे दिशाहीन भटकते रहते हैं। गर्मी के दिनों में मैं ऐसा अपनी आँखों से देखता हूँ। हम लोग इंटीरियर के गाँव में दौरे पर जाते हैं, हमें कहीं पर कोई मरा हुआ जानवर दिखाई पड़ता है, जानकारी करने पर पता चलता है कि वह केवल पानी की कमी से मरा है। हमारे यहाँ पीने के पानी की दिक्कत थी। पिछली सरकार में हम लोगों ने बात की कि हमारे यहाँ कम से कम ट्रेन से पानी पहुँच जाए। कुछ जगहों पर गड्ढों में पानी भर दिया जाए। वहाँ पर टैंकरों से पानी दिया जाए। मवेशी को पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी का और उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने पूरी रूचि लेकर हमारे यहाँ बुंदेलखण्ड में पानी की ट्रेन भेजी। मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। पानी की ट्रेन से समाधान नहीं हो सकता, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन संवेदनशीलता यह है कि अगर वहाँ पर तत्काल कोई व्यवस्था नहीं बन रही है, तो जैसे भी होगा, वहाँ का प्रशासन, पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वह उसे संजीदगी से नहीं ले रही थी। वे हमारे यहाँ क्षेत्र में खनन करने में, अवैध कारोबार करने में तो संलिप्त थे, लेकिन ऐसे संवेदनशीलता के काम करने में उन्हें रूचि

नहीं थी। हमने यहाँ पर आकर गुहार लगाई, यहाँ आकर हमने अपना कष्ट, दर्द बताया, तो मैं गर्व करता हूँ कि मैं उस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जिस पार्टी की सरकार ने मेरे जैसे एक सदस्य की बात को सुनकर इतना बड़ा निर्णय लिया और बुन्देलखण्ड को सभी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए काम किया।

महोदया, मुझे एक बात बताते हुए और हर्ष हो रहा है। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि वर्ष 2024 तक देश के एक-एक गाँव में एक-एक घर में हम पेयजल पहुँचाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से पूरे देशवासियों को इस पर भरोसा है और हमारे बुन्देलखण्ड के एक-एक व्यक्ति को भरोसा है कि अगर आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बोला है कि पीने का पानी पहुँचेगा, तो वह निश्चित रूप से पहुँचेगा। हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, गैस चूल्हा नहीं था, इस प्रकार की जो बातें सरकार ने कहीं थीं, वे वहाँ तक पहुँचीं। घर-घर बिजली पहुँच गई, उज्वला योजना के माध्यम से घर-घर तक गैस पहुँच गई। इन सब चीजों को देखते हुए हमारे यहाँ बुन्देलखण्ड का एक-एक व्यक्ति बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि निश्चित रूप से इस सरकार के पास क्षमता है, मोदी जी के पास एक विजन है और पानी पहुँचेगा।

अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधान मंत्री जी हमारे यहाँ गए थे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी यह संकल्प किया, उन्होंने कहा कि हम बुन्देलखण्ड में वर्ष 2022 तक समस्त गाँवों के एक-एक घर में पानी पहुँचा देंगे। उसका सर्वे हो गया है और तेजी से काम हो रहा है। सर्वे होने के बाद बहुत तेजी के साथ काम शुरू हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पर पानी पहुँचेगा। यह पानी उपलब्ध कहाँ से होगा? सरकार उसका प्रबंधन कर रही है। प्रदेश में बुन्देलखण्ड बहुत बड़ा भू-भाग है। बुन्देलखण्ड का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और वहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। प्रायः यदि देखा जाए तो एक गाँव से दूसरे गाँव की दूरी 8 से 10 किलोमीटर है और आने-जाने में बहुत समय लगता है। वहाँ की कुछ ऐसी टोपोग्राफी है, उसे उबड़-खाबड़ क्षेत्र कह लें, पठारी क्षेत्र कह लें या जंगली क्षेत्र कह लें कि एक गाँव से दूसरे गाँव जाने में कई नाले पार करने पड़ते हैं, जो केवल बरसात तक के लिए सीमित रह गए हैं। मैं यह बात अच्छी तरह से मानता हूँ कि अगर जल प्रबंधन अच्छे तरीके से हो जाएगा तो

हमारे यहाँ इस काम के पूरा होने को बहुत ताकत मिलेगी । हमारे आदरणीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान् गजेन्द्र सिंह शेखावत जी यहाँ पर बैठे हैं । हम लोगों को इस बात की बहुत उम्मीद है, वे बहुत ही ऊर्जावान और बहुत संजीदगी से चीजों को लेने वाले हैं । प्रधान मंत्री जी ने जल संसाधन मंत्रालय का नाम जल शक्ति मंत्रालय रखा है । किसी भी वस्तु का स्वभाव कभी बदलता नहीं है, उसमें गुण हमेशा रहता है, लेकिन जब शक्ति होती है तो गुण उभरकर आ जाता है । जब उसमें शक्ति शब्द जुड़ जाता है तो उसका गुण उभरकर आ जाता है और जिस भाव को लेकर काम किया जाता है, वह पूरा होता है और मैं समझता हूँ कि इसीलिए प्रधान मंत्री जी ने इसका नाम जल शक्ति मंत्रालय किया है । उस क्षेत्र को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए यह बहुत बड़े विजन के साथ काम किया गया है । मैं समझता हूँ कि मेरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए जल शक्ति मंत्रालय वरदान साबित होगा और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से ही हमारे यहाँ की आधे से अधिक समस्याओं का समाधान हो सकता है । मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इस बार की जो सरकार है, हमारे आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी, हमारे प्रधान मंत्री जी के निर्देशन में, उनके विजन के साथ काम करके हमारे बुन्देलखण्ड में देश का यह पहला केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट करेंगे । वे इस काम को बहुत तेजी से शुरू कराने के लिए प्रयासरत हैं । वे इसमें लगे हुए हैं । इस पर काफी प्रयास चल रहा है । पूर्व में आदरणीय उमा भारती जी बुन्देलखण्ड से आती थीं, जब वे मंत्री थीं तो उन्होंने भी बहुत प्रयास किया और बड़ी ताकत के साथ वे भी लगी रहीं । जगह-जगह जाकर, जहाँ डैम बनना है, जहाँ-जहाँ से उसे निकलना है, हम सभी लोग वहाँ पर पैदल जाकर, गाड़ियों से जाकर और हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करके एक-एक बिन्दु पर बड़ी गहनता के साथ अध्ययन हुआ ।

वहाँ जो बाधाएं थीं, उन बाधाओं को दूर करने का काम किया । कुछ थोड़ी-बहुत कमी होगी । अगर यह समय पर पूरा हो जाएगा तो अच्छा होगा । हमारे बुन्देलखण्ड का एक-एक व्यक्ति ऊर्जावान व्यक्ति है । हमारे बुन्देलखण्ड की अनेक परम्पराएं, हमारी संस्कृति हैं । हमारे यहां विश्व की एक बहुत बड़ी धरोहर खजुराहो है, जो एक सांस्कृतिक विरासत है । हमारे पूर्वजों के बनाए हुए मन्दिर

हैं। वहां पर हजारों सालों से लोगों का आना-जाना है और आज वहां दुनिया के हर देश के लोग आते हैं। लेकिन, जब वे वहां से निकलते हैं, तब वे उस सूखे क्षेत्र को देखते हैं। वे देखते हैं कि वहां के दूध देने वाले जानवर, जो वहां के लोगों को कुपोषण से बचा सकते हैं, उनके लिए पीने का पानी नहीं है। जब पानी नहीं मिलेगा तो दूध कैसे उपलब्ध होगा? वहां के बारे में लोगों ने आर्टिकिल लिखे। जब बाहर से लोग वहां आए और फिर बाहर जाकर जब उन्होंने इसके बारे में आर्टिकिल लिखे तो हमारी नौजवान पीढ़ी, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत एक्टिव रहती है, उन लोगों ने हमें वह उपलब्ध कराया कि सांसद जी, हमें यह मिला है, जो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है।

हम लोग जब इसे देखते हैं तो हमें इस बात की बड़ी तकलीफ होती है कि अगर पहले की सरकारों ने इसके बारे में सोचा होता और इसे बड़ी संजीदगी से लिया होता तो निश्चित रूप से यह बात समय के पहले पूरी होती। हमारे बुंदेलखण्ड को हमेशा पिछड़ा माना गया। उसके आधार पर उसे 'बुंदेलखण्ड विशेष' पैकेज भी दिया जाता था। मैंने यहां पर सरकार से कई बार मांग की कि जैसे 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' है, माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य उससे पूरे देश को सिंचित करने का है, लेकिन सबसे पहला लक्ष्य जो लिया जाए, उसमें हमारे बुंदेलखण्ड को सबसे पहले संतृप्त किया जाए। हमारे बुंदेलखण्ड के एक-एक गांव में पानी पहुंच जाए, उसके बाद देश के अन्य भागों में जो काम चले, वह भले ही धीमी गति से चले। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ष 2024 के लक्ष्य को वर्ष 2022 तक कर लिया और तीन सालों में उन्होंने बुंदेलखण्ड को पीने का पानी देने का काम किया है।

मैं अपने आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे बुंदेलखण्ड के लिए वर्ष 2024 से पहले, वर्ष 2022 तक करने का संकल्प ले लेंगे तो अच्छा होगा। हमारा वह सूखा क्षेत्र, वहां से पलायन करने वाला क्षेत्र, वहां की परिश्रमी जनता और वहां के बड़े सज्जन लोग, जो अनेक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, आप वहां का दर्द समझ सकते हैं।

माननीय मंत्री जी राजस्थान से आते हैं । राजस्थान में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं । आप उनसे रूबरू हैं । इसलिए उन समस्याओं को आप अच्छी तरह से समझते हैं ।

मैं समझता हूँ कि हमारे केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए 222 किलोमीटर की यह जो कैनाल बन रही है, इसमें वहां से एक दौधन डैम बन रहा है । उस डैम के बनने के बाद जब यह कैनाल निकलेगी, यहां माननीय मंत्री जी बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जब वह कैनाल वहां से निकले तो मेरे संसदीय क्षेत्र के बगल में दस किलोमीटर दूर पर 25 हजार करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वह मात्र दस किलोमीटर दूर से जा रहा है । वहां पर एक उर्मिल डैम है, मजगोवां डैम है । वहां के लोगों से हमने बात की, उनसे काफी सम्पर्क किया, उसके लिए काफी प्रयासरत रहे, मुझे उम्मीद है कि उस उर्मिल डैम को भी पानी देने का काम निश्चित रूप से आपके माध्यम से होगा, तो जो हमारे बगल से 25 हजार करोड़ रुपये की योजना निकल रही है, उससे हमारे क्षेत्र को आगे काफी पानी मिलना है । वहां उर्मिल डैम, मजगोवां डैम और बेलाताल हैं । इनमें एक डैम है और दो बृहत् तालाब हैं । अगर इन्हें पानी उपलब्ध होगा तो वहां के बहुत बड़े भू-भाग पर जो पेयजल संकट है, वह समाप्त होगा । वहां की कई नगरपालिकाओं को पीने का पानी उस उर्मिल डैम से जाता है । वर्तमान में वहां यह स्थिति है कि वहां पर पानी समाप्त हो गया है । वहां पीने का पानी नहीं है । वहां किसानों के लिए डैम बना था, लेकिन वहां से उसके पानी को मजबूरी में पेयजल के रूप में देना पड़ा । पेयजल के रूप में देने के कारण अब किसानों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है । हमें पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और किसानों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है ।

केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, वह हमारे लिए एकमात्र आशा की किरण है । अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन कर यह यहां से निकला और केन से, दौधन डैम से कैनाल आकर झाँसी में, ओरछा में, बरूआ सागर में जाकर मिला और अगर उसका पानी अगर रास्ते के डैम्स को नहीं मिला तो हमारे पास फिर उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है ।

महोदया, मेरा बहुत विनम्र आग्रह है । सदन के सभी सम्मानित सदस्य यहां बैठे हैं । बहुत अनुभवी लोग यहां बैठे हैं । मैं आपके माध्यम से इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि हमारी जो कठिनाई है, इसके बारे में पूरा सदन जानता है, पूरा देश जानता है, यहां की एक-एक ग्रामीण जनता जानती है । जब विदेशी लोग भी इस बात को जान चुके हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग तो इस समस्या से दिन-प्रतिदिन रूबरू होते हैं, इसके बन जाने से उन्हें इन समस्याओं का सामना करने में सुविधा होगी ।

महोदया, मैं एक आँकड़ा और देना चाहता हूं । हमारे यहां बुंदेलखण्ड, उत्तर प्रदेश में सात जनपद आते हैं । उसमें मेरा संसदीय क्षेत्र है, जिसमें हमीरपुर जनपद, महोबा जनपद और बाँदा का कुछ भाग है ।

इन तीनों जनपदों को मिलाकर आज की डेट में कुल सात लाख गौवंश को किसानों ने अपने घर से छोड़ दिया है । वे मज़बूर हो गए हैं कि कहीं भी जाकर अपना भोजन करें । किसानों के पास खाने के लिए नहीं हैं और वे पलायन कर गए हैं । उनके बुजुर्ग माता-पिता वहां पर हैं । जो नौजवान लोग कुछ काम कर सकते हैं, वे पलायन करके बड़ी-बड़ी जगहों पर चले गए हैं । गांवों में उन जानवरों की सेवा करने के लिए कोई नहीं है । उनको पानी पिलाने के लिए कई जगहों पर दिक्कत है । जब ये जानवर बाहर घूमते हैं तो हिंसक हो जाते हैं । हिंसक जानवरों के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनको अनेक प्रकार की दिक्कतें होती हैं । जब किसान अपने खेत में दिनभर काम करके रात में घर आता है ताकि वह आराम कर सकें, उसने खेत में दिनभर अपना पसीना बहाया है, लेकिन जब वह रात में अपने घर में आता है तो उसको यह चिंता सताती है कि हमारी जो थोड़ी-बहुत फसल है, जिसके लिए हम एक-एक, दो-दो किलोमीटर दूर पाइप से पानी लेकर आए हैं, उस पानी से फसल को सींच कर किसी प्रकार से खाने के लिए अन्न पैदा कर रहे हैं । अगर आलस्य से रात में घर में सो गए, सुबह अपने खेत में जाएंगे तो हजारों गाय आकर खेत को खत्म कर देगी और बाद में हमारे बच्चों भी भूखे मर जाएंगे । हमको कुछ नहीं मिलेगा । इस दर्द को समझते हुए किसान 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा है । किसी भी सरकारी नौकरी में

तथा कहीं भी आदमी को आराम करने का समय है, लेकिन हमारे बुंदेलखंड के एक भी किसान को आराम करने का समय नहीं है ।

अगर किसी के घर में केवल पति-पत्नी हैं, केवल माँ-बेटे हैं, केवल पिता-पुत्र हैं तो एक व्यक्ति घर में रहता है, उसके बाद वह खाना लेकर वहां जाता है और फिर लौटकर आता है । उसके बाद भी अगर कहीं पर दो मिनट की चूक हो गई, वह सो गया, उसको नींद लग गई तो सुबह देखता है कि उसकी खेत साफ हो गए हैं । उसके बाद वह मज़बूर होकर, भले ही इसको दुनिया कायरता कहती है और कायरता है भी, अगर कोई आत्महत्या करता है तो उससे बड़ा कायर कोई नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रात-दिन पसीने बहाकर अपने बच्चों का पेट पालना चाहता है, ईमानदारी की कमाई अपने बच्चों के पेट में डालना चाहता है, जब उसका खेत खत्म हो जाता है तो उसे लगता है कि मैं किसी से भीख नहीं माँग सकता, मैं क्या करूँगा । वह विवश होकर फाँसी लगाने के लिए मज़बूर हो जाता है । मैं जिस योजना के लिए बात बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने प्रारंभ में बोला कि हमारे क्षेत्र की आधे से अधिक समस्याओं का समाधान केन-बेतवा प्रोजेक्ट और पानी की उपलब्धता है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी(बहरामपुर): चन्देल जी, क्या आपके यहां गोकुल मिशन नहीं है?

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: हमारे यहां गोकुल मिशन है । चौधरी साहब, आपने अच्छी बात कही और आप अनुभवी नेता भी है । गोकुल मिशन है और इसके आधार पर कई गौशालाएं बन रही हैं । हमारे पास आँकड़े हैं, जो पूरी तरह से रिकॉर्डेड हैं । अब इन आँकड़ों के आधार पर हमारे क्षेत्र में 24 लाख गायें हैं । इन 24 लाख गायों के लिए गौशाला बन रही है । समाज के लोग भी बना रहे हैं, संत-महात्मा लोग भी बना रहे हैं । जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आयी है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है । हर ग्राम पंचायत को बजट दिया गया है कि आप इस काम को पूरा करें । आज जितने भी काम हो रहे हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन चारे की उपलब्धता नहीं है । पंजाब में भूसे को जला दिया जाता है, पैडी जला दी जाती है, वहां पर यह समस्या है । अगर पंजाब से हमें कोई फ्री में

भी पैडी देगा तो हमारे यहां का किसान उस पैडी को ले जाने के लिए 50 हजार रुपये का भाड़ा नहीं दे सकता है। यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हर क्षेत्र की अपनी-अपनी समस्याएं हैं। अपने देश में पहाड़ी क्षेत्र की अलग समस्या है, कोस्टल एरिया की अलग समस्या है और हमारे यहां की अलग समस्या है। हमारे यहां गोकुल मिशन के माध्यम से बहुत तेजी से काम हो रहा है, बड़े अच्छे ढंग से काम हो रहा है और उसका समाधान भी धीरे-धीरे निकल रहा है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से हमारे यहां जितनी जल्दी पानी उपलब्ध हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि पानी की समस्या दूर हो जाएगी।

जब जानवरों के लिए चारा होगा, क्योंकि आगे आने वाली समस्या यह है कि हम 25 लाख गायों के लिए शेल्टर बना लेंगे, उनके लिए पानी का इंतजाम कर लेंगे, उनके लिए भोजन का इंतजाम कर लेंगे। जब सब चीजों का इंतजाम हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास चारा तथा पानी उपलब्ध नहीं होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कहां से लेकर आएं? उसके बाद अगर किसी प्रकार की बातें होंगी तो मैं समझता हूं कि लोग विवश होंगे और उसमें दिक्कतें महसूस होंगी। जितनी जल्दी जल की उपलब्धता होगी उतनी जल्दी हमारे गौवंश की समस्या का समाधान होगा।

अनेकों प्रकार की बातें हैं, लेकिन मुझे तो अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी है। अभी हमारे कई विद्वान सदस्य इस संकल्प पर बोलने वाले हैं। जब वे बोलेंगे तो पूरे देश की बातें आएंगी। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझते हुए हमारे बुंदेलखंड की इस विकराल समस्या के लिए, मैं आपसे समर्थन नहीं मांगता हूं। हमारी एक बहन बंगाल से आई हैं, अभी वह बोल रही थी। मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर जब कभी भी बुंदेलखंड की बात आए, मैं आप सभी से समर्थन चाहता हूं। आप किसी भी पार्टी से हो, एक्रॉस दी पार्टी लाइन जाकर आप सब लोग वहां पानी के प्रबंध के लिए तथा किसानों की खुशहाली के लिए मैं आपसे मदद की उम्मीद करता हूं।

मुझे उम्मीद है कि जितने लोग भी यहां सदन में चुनकर आते हैं, निश्चित रूप से सेवा करने वाले लोग हैं, वहां पर संघर्ष करने वाले लोग हैं। आप लोग इन समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। यह कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उनका मैनेजमेंट करने की बात है। परम्परागत ज्ञान के कारण से वहां हजारों वर्ष पहले कुछ चीजें बन गईं, जो आज भी वहां पर उपलब्ध हैं। उनके आधार पर वहां लोग जीवित हैं। लेकिन देश के आजाद होने के बाद आज तक जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। हमारे यहां बहुत नदियां हैं, लेकिन तेजी से निकल जाती हैं।

एक समस्या वहां पर और है, लेकिन अब उसमें कमी आई है। पहले की जो हमारे यहां प्रदेश की सरकारें रहीं, मैं आरोप लगाने का आदी नहीं हूं, लेकिन तब हमारे यहां बसपा और सपा की सरकार के समय माइनिंग के माफिया एक्टिव थे। उन माइनिंग माफियाओं ने मिलकर नदियों का स्वरूप बदल दिया। नदियों को पोखरों में तब्दील कर दिया और वहां से रेत निकाल कर अपने खजाने भरने में लगे रहे और वहां की समस्याओं को उन्होंने ठीक प्रकार से दूर करने का काम नहीं किया।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): इससे कोई मतलब नहीं है। ...
(व्यवधान)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : पाण्डेय जी, इससे हमें मतलब है। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : पाण्डेय जी, आप भी अपना नाम दे सकते हैं। जब यह विषय चल रहा है, तो आप भी इस पर बोल सकते हैं। अभी उनको अपनी बात कहने दीजिए। यह अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है कि इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। वे अपना विषय कह रहे हैं। इस देश में खनन माफिया चल रहा है। बहुत राज्यों की यह खबर है।

श्री रितेश पाण्डेय : क्या यह उचित है कि सपा या बसपा को बोला जाएगा?

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : हां पाण्डेय जी, बिल्कुल बोला जाएगा । सपा, बसपा ने लूटा है उत्तर प्रदेश को और बीसों साल तक लूटने का काम किया है । हम खनन माफियाओं से लड़कर यहां आए हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप भी अपना नाम दे दीजिए । पांडेय जी, अभी इंटरवेंशन का समय नहीं है ।

श्री रितेश पाण्डेय : यहां से लांछन लगा रहे हैं । ...(व्यवधान)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदया, यह नदियों से जुड़ा हुआ विषय है और हम नदी की बात कर रहे हैं ।

माननीय सभापति: आप फोकस नदी पर रखिए । खनन माफिया है, सभी जानते हैं । कोई अचम्भे वाली बात नहीं है ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा । अनपार्लियामेंट्री नहीं है ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदया, अगर उनको तकलीफ हो रही है, तो मैं इस बात को रिकार्ड में लाना चाहता हूं । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: रितेश जी, प्लीज बैठिए ।

...(व्यवधान)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदया, बसपा और सपा की सरकार ने वहां पर कितना भ्रष्टाचार और गुण्डाराज किया है । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: पाण्डेय जी, प्लीज बैठिए । रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदया, वहां पर नदियों का स्वरूप बदल दिया । आज भी सीबीआई की इंकायरी चल रही है । वहां के कई ब्यूरोक्रेट्स, अनेक पार्टियों के पॉलिटिकल लीडर्स हैं । ...(व्यवधान) अनेकों प्रकार की दिक्कतें हैं ।

...(व्यवधान) आपको क्यों तकलीफ हो रही है? ...(व्यवधान) आपकी माइन चल रही है क्या वहां पर? ...(व्यवधान) आपकी माइन चल रही है क्या? ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप चेयर को एड्रेस करिए । उधर देखकर बात मत करिए ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदया, मेरा सभी माइनिंग माफियाओं से विरोध रहता है । मैंने सदन में पहले भी इस बात को रखा है कि इन-इन नदियों की रेत को निकालने को लेकर हम लोगों के ऊपर हमले किए । हमें डराने का काम किया गया, खरीदने का काम किया गया । हम डरे नहीं, बिके नहीं, इसीलिए हमीरपुर की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है । हम माफियाओं और भ्रष्टाचारी सरकारों से डरने वाले लोग नहीं हैं । हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं ।

महोदया, यह जो केन-बेतवा का इश्यू है, मैं उस पर अपनी बात कह रहा था और उनसे मदद की उम्मीद कर रहा था । मुझे विश्वास है कि आगे वे मदद करेंगे । इस बात को समझेंगे और निश्चित ही मदद करेंगे । ...(व्यवधान) मैं एक बात और आपके सामने रखकर अपनी बात को पूरी करने का प्रयास करूंगा । ...(व्यवधान) पाण्डेय जी, आपकी मदद की आवश्यकता भी नहीं है । आप ज्यादा मदद मत करिए ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र का ही नहीं, बल्कि देश का विषय है । उनको अपनी बात पूरी कहने दीजिए ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । मैं इस पर बोलना चाहता था । सौभाग्य से मेरे क्षेत्र की समस्या का विषय रखने का मुझे मौका मिला है । मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा । अपने जिस दर्द को मैंने बताया है, मैं उसी पर केन्द्रित रहूंगा, इधर-उधर जाने का प्रयास नहीं करूंगा ।

केन-बेतवा नदी गठजोड़ का जो यह मैटर है, इसको मैंने अन्ना प्रथा से जोड़ने के लिए, वहां के पलायन से जोड़ने के लिए, वहां के रोजगार के लिए और माननीय प्रधान मंत्री जी की संकल्पना कि किसानों की आय 2022 तक दो गुनी करनी है । इन सब चीजों को अगर हम कोरिलेट करेंगे, तो हमारे यहां सबसे

बड़ी आवश्यकता पानी की है । हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी उसके लिए संकल्पित हैं । 2017 में हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था । वे हमारे संसदीय क्षेत्र में आए थे ।

उस समय इसका श्रीगणेश होने वाला था, लेकिन कुछ पर्यावरण की एनओसी में थोड़ा समय लग गया, उस कारण वह प्रोजेक्ट नहीं हो पाया । मैं बुंदेलखंड की जनता का सौभाग्य मानता हूं कि पुनः देश में संवेदनशील सरकार बनी है, एक विजनरी सरकार बनी है । हमारे प्रधान मंत्री जी और जलशक्ति मंत्री आदरणीय श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी यहां बैठे हुए हैं । मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र की गंभीर समस्या को समझते हुए उस पर निश्चित रूप से कोई ठोस कदम उठेगा, जिससे हमारे यहां की समस्या का समाधान होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा । हमारे यहां यमुना नदी एक कोने से बहती है, बेतवा भी बहती है, वहां बहुत चौड़ाई के साथ नदी बहती है ।

हमने पहले भी सदन में मांग की है, चिकासी, हमीरपुर और चिल्ला में, बेना जौहरपुर में, भूमि अधिग्रहण की भी आवश्यकता नहीं है । वहां पर्याप्त मात्रा में जगह है, अगर वहां बैराज बना दिए जाते हैं, सरकार की इच्छा है कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, अगर हम उस नारे के साथ चले, वहां तालाब भी बड़ी तेजी के साथ खोदे जा रहे हैं, सरकार दोनों हाथों से बजट उपलब्ध करा रही है । हमारे बुंदेलखंड के लिए तालाब और कुंए के लिए हर प्रकार की व्यवस्था बन रही है । बेतवा और यमुना नदी में अनेकों ऐसी जगह हैं, हमारे राठ और मौदाह में, हमीरपुर, चरखारी, महोबा और तिनवारी में सभी जगहों पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जहां बिना भूमि अधिग्रहण किए बैराज बनाकर हमारे पूरे क्षेत्र को संतृप्त किया जा सकता है । मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र उससे संतृप्त हो सकता है, बाहर से पानी लाने की आवश्यकता नहीं होगी । बहुत सारा पानी व्यर्थ चला जाता है । आगे हमारे यहां केन नदी यमुना में मिल जाती है, जब यमुना में मिलती है, मेरे संसदीय क्षेत्र में बेतवा यमुना में मिलती है । हमारे यहां से आगे गंगा-यमुना का संगम होता है, फिर हमारा पानी नीचे समुद्र की ओर चला जाता है । जिस पानी को हम रोकने की बात कर रहे हैं, उस दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है । हमारे

बुंदेलखंड में कोई दूसरा संसाधन नहीं है। नीचे ग्रेनाइट की पूरी सीट है, जब लोग वहां ट्यूबवेल का बोर करवाना चाहते हैं, अपनी जमीन बेचकर लोग वहां पर बोर कराते है और मशीन लाते हैं, अपने पैसे से लगाते हैं और सरकार सब्सिडी देती है, तीन-चार सौ फीट तक डस्ट निकलती रहती है। उसका खेत भी बिक जाता है और पानी का इंतजाम भी नहीं होता है। दूसरा अगर कोई ट्यूबवेल बोर कराना चाहता है, उसके दर्द को देखकर, उसकी तकलीफ को देखकर उसके घर में मंथन होने लगता है, एक भाई बोलता है कि खेत न बेचा जाए कहीं पानी न निकले तो क्या होगा, और दूसरा भाई बोलता है कि अगर नहीं बेचा तो हम पानी नहीं लाएंगे और गांव छोड़ कर जाना पड़ेगा, ऐसी अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं। लाखों रुपये खर्च कर, अपने माता-पिता और पत्नी का जेवर बेचकर और अपनी जमीन बेचकर, घर गिरवी रख कर पानी का इंतजाम करते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा-बहुत इंतजाम कर भी लिया है, एक-दो किलोमीटर दूर से पानी लाने का काम करते हैं। आज गायों और मवेशियों के लिए चारा नहीं बचा है। उसके कारण वे दिन भर खेत में परिश्रम करते हैं और रात में भी आकर काम करना पड़ता है, वह राउंड दी क्लॉक खेत में ड्यूटी कर रहा है। मैं समझता हूं कि जैसे हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वैसे ही बुंदेलखंड का किसान अपने खेत में डटा हुआ है, उससे कम स्थिति नहीं है। वहां जब हजारों की संख्या में जानवरों और गायों का झुंड आता है, उसके बाद वे वहां तार लगाएं या फेंसिंग लगाएं या कुछ भी इंतजाम करें, वह उजाड़ता हुआ चला जाता है। बहुत लोग घायल भी होते हैं और अनेकों प्रकार की दिक्कतें होती हैं। मेरे पास पूरा डिटेल था, कई और वक्ता भी हैं, जो इस विषय को रखेंगे। हम लोग बहुत अल्पज्ञानी लोग हैं, यहां बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, हमारा दर्द समझ कर, हमारी पीड़ा में शामिल होकर बुंदेलखंड के समर्थन में खड़े होंगे, यही एक जनप्रतिनिधि का काम है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और बुंदेलखंड की जनता की आवाज को हम केवल यहां रख सकते हैं। अपने अग्रजों के सहयोग से और संवेदनशील सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से काम पूरा हो सकता है। यह काम निश्चित पूरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार और बुंदेलखंड वासियों का पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आपने सत्रहवीं लोक सभा में स्पष्ट और जबरदस्त बहुमत की सरकार जिस आशा

और उम्मीद के साथ बनाई है। मुझे और मेरे क्षेत्र को भरोसा है कि उस आशा और उम्मीद की किरण बहुत जल्द पूरी होगी।

बुंदेलखण्ड से पलायन नहीं होगा। बुजुर्ग माता-पिता वहां अकेले हैं क्योंकि उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उनका इलाज कराने वाला कोई नहीं होता है। उनको इस तरह के दिन न देखने पड़ें, उनके बच्चे बाहर न जाकर यहां काम करें। अगर कोई इस क्षेत्र से बाहर जाए तो पढ़-लिखकर, अच्छी जॉब, अच्छी सर्विस और अच्छे व्यवसाय के लिए जाए न कि मजदूरी करने के लिए, दर-दर भटकने के लिए, किसी झुग्गी में रहने के लिए गांव से बाहर जाए।

यहां बहुत बड़े जमींदार, जिनके पास किसी जमाने में हाथी और घोड़े होते थे, जो गांव में चांदी के सिक्के लुटाते थे, आज उनके घरों के बच्चों की स्थिति यह है कि वे 5,000-10,000 की नौकरी गांव में नहीं करना चाहते हैं। बड़े लोगों के बच्चे 10,000 रुपए की नौकरी नहीं करना चाहते, 20,000 रुपए की नौकरी नहीं करना चाहते। वे कहते हैं कि तब तो हम जनता की मदद करते थे, अब किस मुंह से यह काम करें इसलिए वे अपने क्षेत्र से दूर गुमनामी में जाकर 5,000 रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। मैं उनके दर्द को यहां बयान करने आया हूं।

मैं समझता हूं कि उनके दर्द को समझते हुए हमारी सरकार निश्चित रूप से केन-बेतवा लिंगिंग प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करेगी। इसका ज्यादा से ज्यादा पानी उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है, महोबा जनपद को उपलब्ध कराएगी, इससे हमारे क्षेत्र की अनेक समस्याओं का समाधान होगा।

माननीय सभापति जी, मैं सौभाग्य मानता हूं कि आज आप यहां इस सीट पर विराजमान हैं। भले ही आप दिल्ली से सांसद हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली में जितने भी सांसद हैं, उनके घरों के आसपास हमारी बोली और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। हमें रोज चार-छः लोग मिल जाते हैं। आप उनके दर्द और तकलीफ को समझती होंगी, क्योंकि निश्चित रूप से आपके संपर्क में हजारों लोग आते होंगे।

माननीय सभापति जी, आपने पूरा संरक्षण दिया, मुझे एक सदस्य होने के नाते अपने क्षेत्र की बात कहने का मौका दिया । मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे यहां अपनी आवाज रखने के लिए भेजा है । आपने मुझे उस आवाज को यहां रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं । जय हिंद, जय भारत ।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा): माननीय सभापति जी, संयोग से प्राइवेट मैम्बर बिल के मास्टर लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता अधीर दा यहां बैठे हुए हैं इसलिए बात करने में थोड़ी ज्यादा सुविधा है ।

बशीर बद्र साहब की एक बहुत अच्छी शायरी है –

अगर फुर्सत मिले, पानी की तहरीरों को पढ़ लेना
हर एक दरिया हमारे सालों का अफ़साना लिखता है ।

पूरी दुनिया की सभ्यता नदी घाटी सभ्यता है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे दजला फरात की सभ्यता हो । इसके अलावा जितने भी बड़े शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, वहीं बसे जहां पानी था । आज भी वही देश आगे बढ़ रहा है, वही राज्य आगे बढ़ रहा है, जहां पानी है । चाहे हम अपने देश में गुजरात की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, केरल की बात कर लें । एक जमाना था जब बंगाल बहुत आगे था, क्योंकि वहां कलकत्ता पोर्ट था । कलकत्ता पोर्ट से जो व्यापार होता था, जो माहौल था, उसके कारण उस समय ईस्टर्न इंडिया काफी अमीर हुआ करता था । हमने और आपने धीरे-धीरे ईस्टर्न इंडिया के गौरव को खत्म होते देखा है । राजमहल में औद्योगिक क्रांति के पहले आईसक्रीम की फैक्ट्री वर्ष 1760 में हुआ करती थी और आज आप राजमहल को पहचान नहीं सकते हैं । कलकत्ता के सारे मिल उजड़ गए और इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि पानी की समस्या के बारे में हमने बहुत ही कम सोचा ।

आजादी के बाद यदि किसी एक विषय पर हमने कम सोचा ।

16.45 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the chair*)

राजेन्द्र अग्रवाल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं सभापति के पैनल में आने के लिए, यहां बैठने के लिए । एक बड़ी अच्छी बात आई कि हमारे मित्र भाई पुष्पेन्द्र सिंह जी ने एक ऐसे इलाके के दर्द को यहां उठाने का प्रयास किया और ऐसा बढ़िया संयोग हुआ कि सत्रहवीं लोक सभा में उनको पहला ही मौका इस तरह का मिल गया । केन-बेतवा क्या है? हम पहले उस पर ही जाते हैं, बुन्देलखण्ड पर जाते हैं, क्योंकि उसी से जुड़ी हुई समस्या हमारे संथाल परगना की है । गजेन्द्र सिंह शेखावत साहब मंत्री है, मैं उनसे मिल भी चुका हूँ । बुन्देलखण्ड की समस्या और संथाल परगना जहां से मैं आता हूँ, उसकी समस्या में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है । मेरे यहां जो एक शहर देवघर है, जहां के 5 करोड़ लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, जो शक्ति-भक्ति का सबसे बड़ा केन्द्र है, वहां 1200-1200, 1500-1500 फीट पर बोरवेल फेल है । पीने का पानी नहीं है और जब आदमी को पीने का पानी नहीं है, जानवर को पीने का पानी नहीं है, खेतों में पीने को पानी नहीं है । किस तरह से इस देश को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बताऊँ कि कांग्रेस की नीतियां क्या रहीं और वाटर की क्या जरूरत है? हिन्दुस्तान में एक अनुमान है कि 2050 तक 164 करोड़ लोग हो जाएंगे । एक अनुमान है, हमारे पास दुनिया की 2.4 परसेंट लैंड है । हमारे पास 4 परसेंट पानी है और यदि उसको पूरी दुनिया के परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग-लगभग 17 परसेंट जो पोपुलेशन है, 2.4 परसेंट लैंड है और पूरी दुनिया का 4 परसेंट पानी है । उसमें केवल 2.3 परसेंट फ्रेश वाटर है, जो पीने के काम आएगा, जो खेती के काम आएगा, जो जानवरों को पीने-पिलाने के काम आएगा । 97 परसेंट से ज्यादा, आप समझिए 97.7 परसेंट खारा पानी है, समुद्र का पानी है । केवल तीन महीने बारिश होती है । 90 दिन की बारिश में हमको पूरा मैनेजमेंट करना है, 12 महीने का । लेकिन कोई चिंतित नहीं है । यदि आप उसको परसेंटेज के तौर पर देखेंगे तो ढाई हजार लीटर पानी की आवश्यकता है, यह एक शर्ट बनाने के लिए । यदि मैंने एक कॉटन का शर्ट पहना हुआ है तो उसके लिए हमको ढाई हजार लीटर पानी चाहिए । यदि एक स्लाइस ऑफ ब्रेड यदि

चाहिए तो उसके लिए 40 लीटर पानी की आवश्यकता है । 2400 लीटर पानी चाहिए यदि मुझे 100 ग्राम का चॉकलेट, आजकल के जो बच्चे हैं, हम लोग तो पहले लेमनचूस खा कर ही अपनी जिंदगी बिता लेते थे, लेकिन आज के बच्चे चॉकलेट खाते हैं । यदि 100 ग्राम चॉकलेट खाएंगे तो उनको 2400 लीटर के लिए पानी चाहिए । ये पेपर, जो हम एक पेपर यूज कर रहे है इसको बनाने के लिए 10 लीटर पानी की आवश्यकता है । एक हजार लीटर पानी चाहिए एक किलो दूध के लिए । 3000 लीटर पानी चाहिए एक किलो चावल के लिए और 140 लीटर पानी चाहिए जो यहां कॉफी पीते है हम लोग सेन्ट्रल हॉल में । कहां से आएगा? केन-बेतवा की कहानी सुनी है । बड़ा अच्छा हुआ कि एक टास्क फोर्स बनी, सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में, और उस टास्क फोर्स में सुरेश प्रभु जी मैम्बर थे और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया । सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2002 को एक जजमेंट दिया । उसमें कहा कि- in the said petition, the hon. Supreme Court on 31st October, 2002 had observed:

“We do expect that the programme when drawn up would try and ensure that the link projects are completed within a reasonable time of not more than ten years. We say so because recently the National Highways projects have been undertaken and the same is nearing completion and the inter-linking of rivers is complementary to the said projects and the waterways which are so constructed will be of immense benefit to the country as a whole.”

हमारे प्रधान मंत्री जी और मंत्री गडकरी जी लगातार कहते हैं कि हाइवेज, वाटरवेज, रोडवेज, सभी चलेंगे, तभी इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा । 2002 में एक जजमेंट आया और उसके आधार पर तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक एक्सपर्ट कमेटी कांस्टीट्यूट की । उसमें सुरेश प्रभु जी मेंबर थे, दीपक दास गुप्ता, जो एनएचएआई के रिटायर्ड चेयरमैन थे, वह एक मेंबर थे । के.वी. कामत साहब, जो उस वक्त आईसीआईसीआई बैंक में थे, एक

मेंबर थे, क्योंकि पैसे का भी एक सवाल था कि इतने पैसे कहां से आएंगे । आर.के. पचौरी उसके मेंबर थे । आज के हमारे वित्त मंत्री और कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी भी उसके मेंबर थे । कस्तूरीरंगन और जी.सी. साहू भी उसके मेंबर्स थे । इन लोगों ने एक एक्शन प्लान बनाया । एक्शन प्लान के बारे में हम बाद में बात करेंगे, उस टास्क फोर्स ने 2003 में एक सबसे बड़ी रिकमेंडेशन दी थी :

“The Task Force stated that the peninsular links are the right component to begin with. Top priority links identified by the Task Force on inter-linking of rivers are as under:

1. Ken-Betwa
2. Parvati-Kalisindh-Chambal.”

यह एम.पी. और राजस्थान की नदियों को जोड़ने के लिए थी । यह 2003 की रिकमेंडेशन थी । 2004 में हमारी सरकार चली गई और उसके बाद 2014 तक, दस साल तक कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं रहा । मैं कागज की बात कह रहा हूं । पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी यहां बहुत अच्छा काम करती है । उसकी रिकमेंडेशन्स को हम लोग पढ़ते हैं या नहीं, अधिकारीगण पढ़ते हैं या नहीं, लेकिन एक कागज बन जाता है । रायपति सम्बासिवा राव उस वक्त कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे और वाटर रिसोर्सेज संबंधी स्टैंडिंग कमेटी के वह चेयरमैन थे । संयोग से जब मैं आज पुष्पेन्द्र जी के इस विषय पर भाषण देने के लिए निकल रहा था, चूंकि मुझे कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने की बड़ी गन्दी आदत है, मुझे लगा कि कांग्रेस की ही बातों को उठाया जाए कि कांग्रेस ने क्या-क्या किया । ... (व्यवधान) आपने दस साल आपने क्या किया, वही मैं कह रहा हूं । ... (व्यवधान) भाई, आप जरा हमारी बात को सुनिए । ... (व्यवधान) आराम से सुनिए । ... (व्यवधान) यह कमेटी की रिपोर्ट है । आप लोग यहां हैं, इसलिए बात कही जा रही है ।

माननीय सभापति : यह गन्दी नहीं, अच्छी आदत है ।

डॉ. निशिकान्त दुबे: आप लोग यहां नहीं होते तो कोई सुनने वाला नहीं होता या कोई टोकने वाला नहीं होता और भाषण का कोई मतलब नहीं होता । आप लोगों की एक नेशनल मिनिमम प्रोग्राम कमेटी बनी और उसकी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी हो गईं । मैं रायपति सम्बासिवा राव की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूं । मैं भाजपा-कांग्रेस की बात नहीं करता, जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई, उसे ही पढ़ रहा हूं । यह 2010 की रिपोर्ट है । कमेटी ने लिखा :

“As per the National Common Minimum Programme, the Government has done a comprehensive assessment of linking of the rivers of the country starting from southern rivers in a fully consultative manner. A Committee of environmentalists, social scientists and other experts on ILR has been constituted to advice Government on ILR. The information bulletins of ILR are distributed as a part of mass awareness programme at various seminars, conferences and exhibitions including India International Trade Fair and important public events. The Chairman of the erstwhile Task Force on ILR has written about 1.5 lakh letters elaborating the benefits of ILR to individuals.

For Ken-Betwa link, pamphlets for technical and general public in Hindi and English highlighting the salient features and benefits of the link canal has been distributed in the Ken-Betwa project.”

2008 में यह रिपोर्ट आई थी । इसके बाद कंसल्टेटिव कमेटी कह रही है कि भाई, इसे ऐसे मत करो । जो 2003 की टास्कफोर्स की रिपोर्ट है, उसे आप प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करो ।

“The Committee are also unhappy to take note of the submission made by the Secretary, Ministry of Water Resources during evidence that though making laws under Entry 56 would be legally valid, the Government for the moment does not have any proposal to the effect or to declare

implementation of ILR programme to be expedited in the public interest hereunder.”

यह कांग्रेस के चेयरमैन साहब कह रहे हैं ।

“They are further disheartened to take note of the Secretary’s submission that unless it comes as a recommendation from the Centre-State Relation Commission such a proposal cannot be considered. Since the Centre-State Relation Commission may take some more time in giving its recommendation, the Committee would suggest that instead of waiting for a recommendation by the Commission to the effect, the Government should obtain the opinion/advice of the Ministry of Law as to the interpretation of the provision of Entry 56 in the Union List *vis-à-vis* Entry 17 of the State List. The Committee are of the considered opinion that the creation of a National Authority for inter-linking of rivers as recommended by the Task Force on ILR, the setting of a IWRFC as also inclusion of Ken-Betwa link under the concept of a national project, the enactment of law under Entry 56 of the Union List would be a logical sequence and would go a long way in accelerating the pace of implementation of projects under ILR programme. They would like to be apprised of the opinion of the Law Ministry obtained by Government in this regard at the earliest.”

इसके बाद आपने छः साल सरकार चलाई । आपने कोई काम किया? ... (व्यवधान) आपने पांच साल क्या किया, मैं वही बता रहा हूं । मैं जानता था कि आप यही पूछेंगे । आप नए सदस्य बने हैं तो आप हम से सब कुछ पूछना चाहेंगे, हम सारा विवरण लेकर आए हैं ।

जब मोदी जी प्रधान मंत्री बनें तो उनको लगा कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए । हम ने वर्ष 2002 के पीआईएल का ऑब्जर्वेशन सुनाया है । माननीय सुप्रीम कोर्ट से वर्ष 2012 में उसका एक फाइनल जजमेंट आ गया

।

“The hon. Supreme Court in the matter of Writ Petition No. 512 of 2002 – networking of rivers, along with Writ Petition No. 668 of 2002 delivered a judgement dated 27.2.2012. The hon. Supreme Court had directed that an appropriate body should be created to plan, construct and implement the inter-linking of rivers programme for the benefit of the nation as a whole.”

कांग्रेस के लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी कोई मतलब नहीं है । ब्लैक मनी के लिए एसआईटी बनी । 26 मई, 2014 को माननीय प्रधान मंत्री जी ने चार्ज लिया तो पहली कैबिनेट में सबसे पहला डिसिजन ब्लैक मनी के लिए एक एसआईटी कमेटी बनाने का लिया । माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह भी जजमेंट वर्ष 2012 का था ।

सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने इस पार्लियामेंट में जो भाषण दिया था, उसका जवाब नहीं दिया गया था क्योंकि मैंने उस वक्त के तत्कालीन तीन माननीय सांसदों के ऊपर आरोप लगाया था कि इन लोगों के नाम स्विस बैंक के एकाउंट में, लिंचेस्टाइन बैंक के जो एकाउंट आए हैं, वे डाले गए हैं, चूंकि उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री कोई जवाब नहीं दिए थे । एक हर्ष रघुवंशी थे, जो मेरे भाषण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट चले गए । उस केस को राम जेठमलानी जी और शांति भूषण जी ने लड़ा था और उसके ऊपर से माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया कि आप एक एसआईटी बनाइए । इन्होंने दो साल तक वह एसआईटी नहीं बनाई । ठीक उसी तरह से पानी की बहुत बड़ी समस्या थी ।

सभापति महोदय, इन लोगों की स्थिति और खराब हो गई है । उस दिन मैं देख रहा था, बड़ा हंगामा हुआ, देश में कई पत्रकारों ने भी बहुत लंबा-चौड़ा भाषण दिया कि कहीं से ‘जय श्री राम’ का नाम चल रहा है, कहीं ‘अल्लाह-हू-अक्बर’ का नाम चल रहा है ।

अधीर दा, लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, मैं आपके माध्यम से अपने कष्ट को बयान करना चाहता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं क्योंकि हम और वह

एक समय एक ही राज्य से आते थे । बिहार और बंगाल का बंटवारा वर्ष 1912 में हुआ । कहानी वर्ष 1912 के पहले की है ।

सभापति महोदय, 'वंदे मातरम्' स्वेदशी का नारा था, कांग्रेस की यूनिटी का नारा था ।

17.00hrs

'वंदे मातरम्' को जब ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था, तो वर्ष 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में रवीन्द्र नाथ टैगोर जी की भांजी सरला राय चौधरानी ने 'वंदे मातरम्' को गाया था । वर्ष 1937 में इसी कांग्रेस पार्टी ने 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रीय गीत के तौर पर स्वीकार किया था और उस दिन जब यहां पार्लियामेंट में हंगामा होने लगा और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क साहब ने कहा कि यह इस्लाम विरोधी है, तो ...* और ...* मेज थपथपा रहे थे । क्या ये कांग्रेस पार्टी है?... (व्यवधान) मैं गलत नहीं कह रहा हूं । ये सारी चीजें लोगों ने देखीं, मेरे पास कैसेट है । मैं अपनी सीमा जानता हूं और मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, यह भी जानता हूं । यदि ए.आर. रहमान 'वंदे मातरम्' गा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है । शफीकुर्रहमान मुसलमान हैं, तो क्या ए.आर. रहमान मुसलमान नहीं हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : रिवर इंटरलिंगिंग बहुत अच्छा इश्यू है और गंभीर मुद्दा है । हम सभी को इसमें भाग लेना चाहिए और इसे सुलझाना चाहिए । यह हमारी नेशनल रिस्पोंसेबिलिटी है । लेकिन इस विषय के बीच आप कहां से कहां आ रहे हैं, आप स्वयं देखिए । उस दिन शपथ लेने में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ । हमारे शपथ ग्रहण में बाहर के सारे लोगों के लिए यह आलोचना का मुद्दा बनता है, तो यह हमारे लिए हानिकारक है । मैडम सोनिया गांधी ने नहीं किया, बेकार बातें करते हैं । ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अधीर रंजन जी, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए । माननीय सदस्य 15वीं लोक सभा में फाइनेंस बिल पर बोल रहे थे । तब भी इन्होंने यह बात कही थी, क्योंकि नोटिस लिया जाता है ।

निशिकांत जी हमारे बहुत अच्छे वक्ता हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का थॉट प्रोसेस बदल गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी : उस दिन किसी ने कहा 'वंदे मातरम्' और इन्होंने मेज थपथपाया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अधीर जी, 'नदी जोड़ो' की बात सबसे पहले डॉ. अम्बेडकर जी ने रखी, उसके बाद अटल जी ने रखी। कांग्रेस भी कभी न कभी इसके समर्थन में थी, लेकिन वर्ष 2004 से 2014 के बीच में समर्थन में नहीं थी। वर्ष 1937 में 'वंदे मातरम्' के पक्ष में थी, लेकिन अब नहीं है, थॉट प्रोसेस बदल गया, यही बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य ने जिनके नाम का उल्लेख किया है, वे सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनका नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति जी, मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता की बात मान ली कि ताली नहीं बजाई, लेकिन उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि अशफाकुल्ला 'वंदे मातरम्' कहते हुए फांसी पर लटक गए। ए.आर. रहमान 'वंदे मातरम्' गाते हैं। क्या अशफाकुल्ला मुसलमान नहीं हैं, क्या ए.आर. रहमान मुसलमान नहीं हैं? क्या इस्लाम को केवल शफीकुर्रहमान जानते हैं। इस पार्लियामेंट में यदि 'वंदे मातरम्' का विरोध होता है, तो उसका सभी मिलकर विरोध क्यों नहीं करते हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम पर क्या देश चलता है?

श्री अधीर रंजन चौधरी: हाउस में 'वंदे मातरम्' की सबसे बड़ी गूंज होती है। सारे हिंदुस्तान को 'वंदे मातरम्' कांग्रेस पार्टी ने सिखाया।

डॉ. निशिकान्त दुबे: सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि यह 27 फरवरी, 2012 का जजमेंट आया और कांग्रेस पार्टी दो साल तक बैठी रही। इसके बाद माननीय मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी की सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी मिली। "The Union Cabinet, in its meeting held on 24th July, 2012, has approved the constitution of the Special Committee on interlinking of

rivers in the light of the judgement dated 27.2.2012 of the Honourable Supreme Court.”

इस बात को सभापति जी मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनिका टैगोर साहब को बताना चाहता हूं । मैं बताना चाहता हूं कि हमने इसके बाद क्या किया । “The Special Committee has been constituted by the Ministry of Water Resources, RD and GR vide Gazette Notification dated 23rd September, 2014. Thirteen meetings of the Special Committee on the interlinking of rivers have been held.” उसकी डेट 17 अक्टूबर, 2014, 6 जनवरी, 2015, 19 मार्च 2015, 14 मई, 2015, 13 जुलाई, 2015, 15 सितम्बर, 2015, 18 नवम्बर, 2015, 8 फरवरी, 2016, 29 अप्रैल, 2016, 26 जुलाई, 2016, 9 नवम्बर, 2016, 8 मार्च, 2017 और 27 जुलाई, 2017 है । क्या इससे ज्यादा भी कुछ किया जा सकता है । ... (व्यवधान) मीटिंग तो पूरे देश के लिए हो रही है । सुप्रीम कोर्ट ने केवल केन-बेतवा नदी के लिए ही नहीं कहा है ।

इसके बाद क्या हुआ? इसकी एक रिपोर्ट आई । इस रिपोर्ट के बाद हमने केन-बेतवा का काम चालू किया । हमने मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से एम.ओ.यू. कराया । आप कहेंगे कि यह एम.ओ.यू. होने में लेट क्यों हो गया । मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यहां माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार थी । एक बिजली संयंत्र - बीना रिफायनरी को पानी देना है या नहीं देना है, इसके लिए दोनों राज्यों के बीच यदि पानी है, तो सभापति महोदय, यदि हम लोगों को पीने का पानी देंगे, किसानों को पानी देंगे, जानवरों को पानी देंगे, तो लोगों को खाने के लिए भी रोज़गार देंगे । इस पानी का उपयोग जितना किसान के लिए ज़रूरी है, उतना ही पीने के लिए भी ज़रूरी है ।

सभापति महोदय, यदि कोई सरप्लस पानी मिलता है, तो उसको हम इंडस्ट्री के लिए यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है । झारखंड के नाते, संथाल परगना के नाते हम लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं । बिहार और

झारखंड के बंटवारे के बाद सबसे बड़ी समस्या झारखंड की हो गई कि सब से ज्यादा माइन्स और मिनरल्स - इस देश का लगभग 50 परसेंट माइन्स और मिनरल्स झारखंड में है । इस देश में कांग्रेस के बड़े नेता रेल मंत्री रहे हैं । आज भी रेल का 40 परसेंट से ज्यादा रेवेन्यु केवल एक राज्य - झारखंड देता है । यदि झारखंड रेवेन्यु देना बंद कर दे, तो इस देश में शायद रेल में भी ताला लग जाए । हमारे यहां पिछले 15 सालों से हम एक इंडस्ट्री के लिए तरस रहे हैं । हम इंडस्ट्री नहीं बना पा रहे हैं । हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसी पानी के कारण नहीं बना पा रहे हैं । जब बिहार और बंगाल एक साथ था, तो बिहार की ज़मीन पर बंगाल ने तीन-तीन डैम बना लिए । पंचेत डैम बन गया, मैथन डैम बन गया, मसानजोर डैम बन गया । ये हमारी ज़मीन पर हैं, झारखंड की ज़मीन पर हैं ।

सभापति महोदय, वे सारी नदियां हमारे यहां से निकलती हैं । मयूराक्षी नदी जिस पर मसानजोर डैम है, वह मेरी लोक सभा देवघर से निकलती है । मैथन और पंचेत डैम दामोदर नदी पर हैं। दामोदर नदी हमारे यहां से, पलामू से निकलती है । आपको आश्चर्य होगा कि 1978 में ज्योति बसु और कर्पूरी ठाकुर का जो पानी का बंटवारा हुआ था, उसमें बंगाल सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट किया कि वह हमें दो डैम बनाकर देगी । 1978 से लेकर आज तक 40-41 सालों के बाद मैं इस सदन में बोल रहा हूं कि बंगाल सरकार ने उस बात को पूरा नहीं किया । हमारा पानी है, जो सारा का सारा पानी बंगाल यूज़ करता है । हमारे लोग विस्थापित हुए, हमारी ज़मीन चली गई । हमारे यहां डी.वी.सी. का पावर प्लांट है, लेकिन उसका सारा का सारा उपयोग बंगाल कर रहा है । इस तरह की सिचुएशन में हम लोग जीने और मरने के लिए बाध्य हैं । यही हाल बुंदेलखंड के लोगों का है । आज तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा । इसके लिये कौन सोचेगा? सवाल जो इस लोक सभा में, इस पार्लियामेंट में है, कि गरीब लोग आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? पानी का बंटवारा सही रास्ते से होगा या नहीं होगा? पानी, जो कि एंट्री-56 का एक विषय है, उस पर राज्य और केन्द्र के बीच में वह सहमति बनेगी या नहीं बनेगी?

माननीय मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया है, जिसे गंगा को भी स्वच्छ करना है, यमुना को भी स्वच्छ करना है, कृष्णा, गोदावरी, सब को स्वच्छ करना

है। इसी तरह गंगा बेसिन की जो ट्रिब्यूटी है या जो जमुना की ट्रिब्यूटी है, चाहे वह अजय हो, चाहे वह महानंदा हो, चाहे वह गेरुआ हो, चाहे वह डडुआ हो, चाहे पतरो हो, चाहे जयंती हो, इस तरह की नदियों के पानी का बंटवारा होगा या नहीं होगा? आप यह समझें कि मेरे लोक सभा क्षेत्र से एक नदी निकलती है - चानन। उस पर 1970 में डैम बन गया था। उस डैम से मेरे लोक सभा के गोड्डा जिले को पानी आना है।

हमने कैनाल बना ली। 85 किलोमीटर की कैनाल बन गयी। वर्ष 1970 से आज तक हम जूझ रहे हैं, गोड्डा में एक बूंद पानी नहीं है। चांदन से जो हाई लेवल कैनाल बिहार को बनाकर वर्ष 2000 के बाद झारखण्ड को देना था, उसके पहले बिहार और झारखण्ड एक ही था। इस तरह के अन्याय यदि छोटे-छोटे राज्यों के साथ होंगे, छोटे-छोटे इलाकों के साथ होंगे, गरीब इलाकों के साथ होंगे तो मैंने इसीलिए इस विषय पर बोलने का फैसला किया। बुन्देलखण्ड की स्थिति वही है जो हमारे यहां संथाल परगना की है। सेम वही सिचुएशन है। 80 परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 75 परसेंट महिलाएं मालन्यूट्रीशन की शिकार हैं, एनिमिक हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं, वे जिन्दा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। हैल्थ फैसिलिटी नहीं है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो इस देश 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से हमारे सारे के सारे जिले हैं। 24 जिलों में से 21 जिले झारखण्ड के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि हम पीने का पानी दे पायेंगे कि नहीं दे पायेंगे। किसानों को पानी दे पायेंगे कि नहीं दे पायेंगे। झारखण्ड एक ऐसा राज्य है, जहां केवल 12 परसेंट जमीन सिंचित है और वही हाल बुन्देलखण्ड के लोगों का है। यदि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहां है, जो पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी और अनुराग शर्मा जी अभी नए सांसद बने हैं झांसी के और उन्होंने अपनी ट्रेन छोड़ी इसी डिबेट में भाग लेने के लिए। यदि आप झांसी, बुन्देलखण्ड, खजुराहो, ललितपुर और महोबा के एरिया को देखेंगे तो आपको रोना आएगा कि आजादी के 70 साल बाद हमने इसी के लिए यह किया है। के.एल. राव आप ही के इरिगेशन मिनिस्टर थे। एक पायलट थे दस्तूर, उन्होंने 1970-72 में एक कल्पना की, लेकिन क्या वह कल्पना पूरी हो पाई? क्यों नहीं हो पाई? मैंने आपको केन-बेतवा की कहानी बता दी। आप

समझिए मैंने एक सांसद होने के बावजूद भी, महुआ मोइत्रा जी कुछ बोलेंगी और मैं उनको बोलने का पूरा मौका दूंगा । मैं एक ऐसा सांसद हूं जिसने बिहार सरकार के खिलाफ भी और बंगाल सरकार के खिलाफ भी पी.आई.एल. की हुई है । मेरा केस चल रहा है । बंगाल सरकार को नोटिस मिला है । बंगाल सरकार ने अभी इण्टरस्टेट कौंसिल बैठक हुई, उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने मीटिंग की तो बंगाल सरकार ने उसमें एक्सेप्ट किया कि वर्ष 1978 में जो डैम उनको बनाकर बिहार सरकार को देना था और झारखण्ड सरकार को देना था, वह उन्होंने नहीं दिया । इस कारण से समस्या है । उनको पता है । आपको मैं दिखाने ले चलूंगा, आप पार्टी की प्रवक्ता हैं । मैं आपके माध्यम से महुआ मोइत्रा जी को अपने यहां आमंत्रित करता हूं कि जो मसानजोर डैम है, वह मेरे यहां की नदी है । हमारा पानी आपके यहां जा रहा है, हमारे किसानों के लिए पानी नहीं है । मैथन और पंचेत हमारे यहां है । आपके बंगाल का एक इंच जमीन नहीं है, सारी की सारी जमीन झारखण्ड की है, लेकिन सारा का सारा पानी आप उपयोग कर रहे हैं । क्योंकि हमारे यहां केवल 14 मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं । मैं अभी भाषण दे रहा हूं तो शायद एकाध ही यहां पर मौजूद होंगे । आपके यहां इतनी बड़ी संख्या है, 42 लोग हैं तो आप लोग दबाव देकर हमारा पानी खींचकर ले जा रहे हैं । ... (व्यवधान) इतने वर्षों के बाद मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को, देश की जनता को और नए जो जल शक्ति मंत्री हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार कम से कम पानी एक बड़ा विषय है । पीने का पानी और सिंचाई का साधन बड़ा विषय है, क्योंकि किसी जमाने में आश्चर्य होगा कि आज से 500-550 साल पहले मुगलों ने इसके ऊपर काम किया था । जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है, जिस इलाके से सभापति महोदय आप आते हैं, उन मुगलों ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पानी देने के लिए आज से 500 साल पहले उसको बनाया था । आज भी आप समझिए कि हम लोग जिस हर की पौड़ी में स्नान करते हैं, वह अंग्रेजों की बनायी हुई है, उसको हमने नहीं बनाया है । वह गंगा नहीं है, गंगा वह डाइवर्टिड है, वह कैनाल है । कैनाल सिस्टम, जिसके कारण पूरा का पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आज आप समझिए खुशहाल है । के.एल. राव ने जो प्लान बनाया था, दस्तूर ने जो प्लान बनाया था, इसी कांग्रेस पार्टी ने

प्लान बनाया था, उसने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया । कई ऐसे प्लान हैं । ये पानी का प्लान है । मैं आपको बताऊं कि उसी तरह से नेहरू जी के बारे में ये बहुत बोलते हैं । नेहरू जी विज्ञानी थे, मतलब बड़े थे, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस देश को बनाने में । पहले प्रधान मंत्री थे, निश्चित तौर पर बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है । लेकिन आप समझिए कि उन्होंने कहा था कि हम मणिपुर के रास्ते बर्मा जाएंगे, बर्मा से हम इण्डोनेशिया चले जाएंगे, थाईलैण्ड चले जाएंगे, मलेशिया चले जाएंगे, सिंगापुर चले जाएंगे, मनीला तक हम रोड बना देंगे ।

वर्ष 1962 से लेकर आज तक हम क्यों नहीं बना पाए हैं? क्यों मोदी जी के भरोसे छोड़ दिया है?... (व्यवधान) हम बना रहे हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ । हम बना रहे हैं । उस पर काम शुरू हो गया । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से तीन-चार बातें कहना चाह रहा हूँ । जो टास्क फोर्स की कुछ रेकमेण्डेशंस हैं, पूरे देश भर के लिए, जैसे पहला रेकमेण्डेशन था कि “Transferring surplus flows from the rivers of Mahanadi, Godavari to deficit basins of Krishna, Pennar, Cauvery and Vaigai...”, जिसके कारण ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु और उसके साथ नॉन लिंक जुड़ना था । मैं तमिलनाडु की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यह देश की बात हो रही है ।

माननीय सभापति : आप बहुत विद्वान सांसद हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, पर बाकी माननीय सदस्यों को भी मौका मिल जाए । मैं पहली बार आपको टोक रहा हूँ, टोक भी नहीं रहा हूँ, केवल आपसे निवेदन कर रहा हूँ ।

डॉ. निशिकान्त दुबे : महोदय, बस पांच-सात मिनट बोलूंगा, वैसे तो मैं एक घण्टा बोलता हूँ, लेकिन आज मैंने छोड़ दिया है ।

माननीय सभापति : मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको कहा है । बाकी लोग भी बोलना चाहते हैं ।

डॉ. निशिकान्त दुबे : महोदय, दूसरा, “Transferring water from west-flowing rivers to the benefit of Karnataka, Tamil Nadu and Kerala...” इसके बाद ये केन-बेतवा, जिसके ऊपर कि इतना बड़ा डिस्कसन है, जिसके

लिए पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल साहब और अनुराग शर्मा साहब और उनकी पूरी टीम और साथ में गजेन्द्र सिंह शेखावत साहब यहां बैठे हुए हैं, कटारिया साहब भी हैं। वैसे आजकल जब से मंत्री बने हैं तो इनके पास हमारे जैसे लोगों के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन शायद केन-बेतवा के लिए फुर्सत होगी। मैं यह कहा रहा हूं कि पहला प्रोजेक्ट, जिसको कि हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर डालना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचें। मैं इसके अलावा बहुत ज्यादा न बोलते हुए अपने क्षेत्र के बारे में, जैसे मैंने कहा कि मैं जिस संधाल परगना से आता हूं, वहां एक कलेक्टर, कमिश्नर और एस.डी.ओ. सभी रहे, कास्टेयर सर। वह वर्ष 1890 में रिटायर हुए थे। उनकी एक किताब है कलेक्टर्स डायरी, जो उन्होंने 1908 में लिखी। उन्होंने लिखा कि हमने संधाल परगना में सब कुछ ठीक करने का प्रयास किया और जितना हो सकता था, उतना हमने प्रयास किया। लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा था, जिसको मैं नहीं सुधार पाया। यह वर्ष 1890 की कहानी उन्होंने बतायी और मैं वर्ष 2019 में बोल रहा हूं, ठीक 130 साल बाद। जितनी इस देश की आबादी है, उतने साल बाद, 130 साल बाद। यह जो डिपार्टमेंट है इरिगेशन और पी.एच.जी. का, जो कास्टेयर साहब ने 1890 में लिखा, आज भी 130 साल बाद प्रत्येक राज्य में वहीं का वहीं है। यहां सारे सांसद मौजूद हैं। कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन वहां के इंजीनियर की स्थिति यही है। डी.पी.आर. बनते-बनते एक इंजीनियर का तबादला हो जाता है, दूसरा कंसल्टेंट आता है, कंसल्टेंट चला जाता है। मेरा संधाल परगना है, जहां की सारी नदियां गंगा में जाती हैं और गंगा समुद्र में मिल जाती है। हमारे यहां जो नदियां हैं, चाहे वह अजय हो, चाहे पथरो हो, चाहे जयंती हो, चाहे गढ़वा हो, चाहे गेरुआ हो, चाहे कजिया हो, चाहे हरना हो, चाहे त्रिवेनी हो, चाहे चानन हो, चाहे बड़ुआ हो, ये सारे प्रोजेक्ट इंटर-लिंग्किंग ऑफ रिवर्स के लिए पड़े हुए हैं। वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। 1200-1500 फीट पर भी ग्राउण्ड वाटर नहीं है। ग्राउण्ड वाटर मैनेजमेण्ट इस देश में मोर और लैस फेल है। हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति ने एक अच्छा काम किया कि लोगों को खाना, पीना, खिलाना शुरू किया। हम लोग फूड सिक्योरिटी के बारे में सेल्फ सस्टेण्ड हैं, लेकिन जो सबसे भारी नुकसान इस हरित क्रांति ने किया, वह यह कि वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए। इस कारण ग्राउण्ड

वाटर प्रत्येक साल नीचे चला जा रहा है । उसके मैनेजमेंट का किसी भी राज्य ने कोई संज्ञान नहीं लिया है । ग्राउण्ड मैनेजमेंट के बारे में क्या करेंगे । जो पानी तीन महीने पड़ता है, 90 दिन पानी पड़ता है और आदमी को पानी की आवश्यकता 365 दिन है । उस पानी के लिए क्या करेंगे? संधाल परगना जैसा जो पिछड़ा इलाका है, जो बुंदेलखंड से मिला हुआ इलाका है, उसमें पुनासी जैसा डैम बन रहा है । वर्ष 1980 से वह डैम बन रहा है । 26 करोड़ की योजना एक हजार करोड़ की हो गई है । बुढ़ई डैम का वर्ष 1978 में मधु लिमये जी ने उसका शिलान्यास किया था, वह आज भी नहीं बन पा रहा है । वर्ष 1978 में सुगाबथान डैम बन रहा था, वह नहीं बन पा रहा है । बंगाल हमारे साथ जो अन्याय कर रहा है, मसानजोर के तौर पर, पंचायत के तौर पर ।...(व्यवधान) इस पानी का क्या होगा? जो बिहार हमारे साथ अन्याय कर रहा है । चानन का पानी जो हमारे गोड्डा में नहीं आ रहा है, इसलिए हमारे जैसे छोटे राज्यों के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं । किसानों को पानी नहीं है, जानवरों को पानी नहीं है । उसके लिए आप किस तरह की व्यवस्था करेंगे?

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि हम लोग छोटे राज्य के हैं । हमारे जैसे लोगों की आवाज बहुत दब जाती है । यहां बड़े राज्यों का आधिपत्य है । उस आधिपत्य से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, जो वर्ष 2014 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने शुरू किया है, उसमें लुक ईस्ट पालिसी के तहत झारखंड भी उसका एक पार्ट है । आप झारखंड और बुंदेलखंड को एक साथ रखकर कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? कैसे हम लोगों के साथ न्याय करेंगे । अंत में मैं केवल एक कविता कहूंगा कि-

खेत-खेत फैला सन्नाटा है, गागर घाट तुम्हारा है,

घाट-घाट में निर्मम प्रहार, अन्न कहां से लाओगे आप ।

अन्न कैसे आएगा? हम गरीब कैसे खाना खाएंगे? आपसे यही आग्रह है कि हमारे क्षेत्र के ऊपर ध्यान दीजिए । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं । जय हिन्द, जय भारत ।

श्री निहाल चन्द (गंगानगर) : माननीय सभापति महोदय, आपने 17वीं लोक सभा के पहले सत्र में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी ने जो संकल्प लिया है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सूखा है, उसके लिए सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में विराजमान है। यहां पर सूखा भी है, यहां पर पानी भी है और यहां पर बाढ़ भी आती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, जो सूखे से इतने प्रभावित हैं, उनमें सिंचाई हेतु तो क्या पीने की पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, राजस्थान प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है, जो पूरा का पूरा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान प्रदेश में पीने के पानी की भी समस्या आती है, खेती तो बहुत दूर की बात है। बुंदेलखंड का आपने जिक्र किया है। सरकार ने पीने के पानी के लिए अलग-अलग समय में अलग-अलग व्यवस्था की है। केन्द्र में हमारी सरकार है। वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक जिस तरीके से रेलवे विभाग ने पीने के पानी के लिए जो सहयोग किया है और रेलगाड़ियों द्वारा पानी भिजवाया है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है।

मैं समझता हूं कि हर गांव के गरीब के लिए, हर गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अगर किसी ने पहली बार प्रयास किया है, तो वह केन्द्र की सरकार और देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया है। यह संकल्प एक पानी का संकल्प है। इस देश के अंदर 12 करोड़ किसान जो खेतों में बसते हैं, अगर उनकी अर्थव्यवस्था को किसी ने सुधारने की शुरुआत की थी, तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अटल जी ने नदियों से नदियों को जोड़ने की बात की थी। लेकिन उनका राज चला गया और राज जाने के बाद जब इधर पर कांग्रेस पार्टी के लोग आए, तो नदियों से नदियों को जोड़ने की बात की और उस स्कीम को अगर किसी ने बंद करने का काम किया है, तो वह कांग्रेस पार्टी के राज में किया गया है। मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है कि अगर अटल जी का वह सपना पूरा हो गया होता, तो चन्देल साहब को आज इस संकल्प को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर सूखा हो, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था हो, खेती के लिए पानी की व्यवस्था हो, अगर ऐसा काम कोई

कर सकता है, तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। मैं कह सकता हूँ कि आज से पहले और आज तक भारत में नहर पर 31.4 प्रतिशत, कुंओं पर 22 प्रतिशत, तालाबों पर 4.7 प्रतिशत, नलकूप पर 36.6 प्रतिशत और अन्य साधनों से 5 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। सूखा पड़ता है, पीने के पानी की परेशानी आती है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जहां से मैं आता हूँ, 66 प्रतिशत भाग सिंचाई पर निर्भर है और मैं समझता हूँ कि जहां पर सूखा पड़ रहा है, उसके लिए आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी ने पिछली बार 53 हजार करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना की जो शुरुआत की थी, जो बजट का प्रावधान किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर के दिखाने का काम किया था। मैं इस सरकार को और देश के प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि किसान के खेत में पूरा पानी पहुंचे, इसके लिए अगर किसी ने व्यवस्था की है तो भारतीय जनता पार्टी के राज ने की है।

सभापति महोदय, मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, उस प्रदेश में तीन नहरें हैं। एक एशिया की सबसे बड़ी नहर राजस्थान कैनाल है। आदरणीय मंत्री जी भी राजस्थान से ही हैं। दूसरी भाखड़ा है और तीसरी गंग कैनाल है। तीनों नहरों के लिए पहली बार आजादी के बाद अगर किसी ने पैसा दिया तो भारतीय जनता पार्टी के राज ने और नरेन्द्र भाई मोदी जी ने दिया है। मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान कैनाल जो इतनी बड़ी नहर है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, उसके लिए 3200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान दिया है। सारी की सारी नहरों का नवीनीकरण करने काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पहली बार इतना पैसा नहरों के नवीनीकरण के लिए दिया गया है। हमारे गजेन्द्र सिंह जी, जो जल-शक्ति मंत्री हैं, इनकी देख-रेख में काम हो रहा है। पहली बार हरी का बैराज, जो पंजाब में है, हमने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से निवेदन किया, सभापति महोदय, सन् 1952 में हरि का बैराज बना था। अब पानी कम कैसे हो रहा है, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसान के खेत में अगर पूरा पानी पहुंचाने का काम करेंगे तो नहर बिल्कुल साफ होनी चाहिए। वहां के डैम बिल्कुल साफ होने चाहिए। पहली बार 64 करोड़ रुपये दे कर, सन् 1952 के बाद 64 करोड़ रुपये उसमें दिए और हरि के बैराज को साफ-सुथरा किया। जब सन् 1952 में हरि का

बैराज बना था, तब 66 हज़ार क्यूसेक पानी उसमें आ रहा था । अब मात्र आठ हज़ार क्यूसेक पानी उसमें आ रहा है । यह हरि के बैराज की स्थिति थी । लेकिन पहली बार हमने उसको साफ किया है । मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से नहरों के लिए काम होता गया, नदियों के लिए काम होता गया तो बुंदेलखंड की जो स्थिति माननीय चंदेल साहब बता रहे हैं, वैसी स्थिति कभी पैदा नहीं होगी । मैं जिस राज्य से आता हूँ, सभापति महोदय, हमारे यहां राजस्थान कैनाल है, जिसका पानी पंजाब से आता है । हरियाणा और पंजाब जब एक ही राज्य था, तब से ले कर आज तक हमारे चार बार अंतर्राज्यीय जल समझौते हुए हैं । पहला समझौता 29 जून, सन् 1955 को प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ । दूसरा समझौता 13 जनवरी, सन् 1959 को पंजाब और राजस्थान के बीच में सतलुज नदी के लिए एक समझौता हुआ । वह भी नेहरू जी के समय में हुआ । तीसरा समझौता 31 दिसंबर, 1981 को इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ, जिसमें राजस्थान और पंजाब के मुख्य मंत्री जी भी शामिल थे । चौथा समझौता 24 जून, 1985 को राजीव गांधी जी के प्रधान मंत्री कार्यकाल में हुआ । चार बार अंतर्राज्यीय समझौते होने के बाद भी राजस्थान को आज भी पूरा पानी नहीं मिल रहा है । राजस्थान का पॉइंट 6 एम.ए.एफ. यानी मिलियन एकड़ फिट पानी आज भी पीछे पड़ा है, हरि के बैराज में है, पंजाब के पास में है और राजस्थान को आज तक पूरा पानी नहीं मिला है । हमारे जल शक्ति मंत्री राजस्थान से हैं, ये अब पूरी कोशिश करेंगे कि राजस्थान को उसका पूरा पानी मिल सके । वैसे तो ये पूरे भारत के जल शक्ति मंत्री हैं, लेकिन हमारे राजस्थान के रहने वाले हैं तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान को पॉइंट 6 एम.ए.एफ. पानी जो राजस्थान के हिस्से का पानी बनता है, उसको राजस्थान को दिलाने का वे काम करेंगे, चाहे वे दोबारा दोनों मुख्य मंत्रियों से बात करें या तीनों मुख्य मंत्रियों से बात करें, लेकिन राजस्थान को उसका पूरा पानी मिलना चाहिए । राजस्थान का किसान जिस तरीके से जीवन जी रहा है, वह सारी दुनिया जानती है । भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जो बना था, उसका चेयरमैन तीन राज्यों से बनता है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों से बनता है । तीनों स्टेटों से एक बार हरियाणा का बनेगा, एक बार पंजाब का बनेगा, एक बार राजस्थान का बनेगा । लेकिन मंत्री जी आज तक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन

राजस्थान से एक बार भी नहीं बना । एक बार हरियाणा का बनता है, एक बार पंजाब का बनता है लेकिन समझौते में एक बार राजस्थान, एक बार हरियाणा और एक बार पंजाब का होना चाहिए था । एक बार भी बीबीएमबी का चेयरमैन राजस्थान का नहीं बना । मेरा आपसे आग्रह है कि जब रोटेशन घूमता है तो राजस्थान का भी उसमें नम्बर आना चाहिए ताकि उसमें राजस्थान को कुछ फायदा मिल सके ।

सभापति महोदय, मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान प्रदेश में 'मुख्य मंत्री जल स्वाभिमान अभियान' की शुरुआत की थी । उससे राजस्थान को पानी का बहुत बड़ा फायदा मिला और मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में आज जल स्तर बढ़ा हुआ है । पहली बार ऐसा हुआ है कि डेढ़ से ढाई प्रतिशत की जल स्तर की बढ़ोतरी, सिर्फ एक इस योजना से हुई थी । मैं समझता हूँ कि यह योजना एक बहुत अच्छी योजना है । अगर इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाए तो पानी के जल संग्रह में बढ़ोतरी होगी । माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा, वैसे मैं माननीय मंत्री जी से कल मिलकर आया था, मैं एक बहुत तगड़ी संवेदनशील बात बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान एक सीमवर्ती क्षेत्र है । मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी सहित 13 जिले, हम लोग पंजाब के इंदिरा गांधी नहर का पानी पीते हैं, जिसमें आप भी हैं, जिसमें पंजाब के मुख्य मंत्री भी हैं, आप भी हैं । 13 जिले पंजाब का पानी पीते हैं । पंजाब में लुधियाना के पास 383 जो फैक्टरियाँ लगी हैं, उन फैक्टरियों का केमिकल युक्त गंदा पानी, चमड़े का पानी, सारा का सारा केमिकल युक्त गंदा पानी फैक्टरियों का समुद्र में गिर रहा है । उसका पानी हम लोग पी रहे हैं । एक बुड्ढा नाले के नाम से वहाँ पर एक नहर है । ऐसी 30 नहरें उस गंदे पानी को लाकर हरिके बैराज में डाल रही है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे क्षेत्र में कैंसर फैल रहा है । सभापति महोदय, बठिण्डा से बीकानेर के लिए एक ट्रेन चलती है, उसका नाम कैंसर ट्रेन हो गया है । इतनी भयानक बीमारियाँ फैल रही हैं और मैं समझता हूँ कि 383 गंदी फैक्टरियों का पानी अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाला भविष्य क्या कहेगा, यह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है ।

कल मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करने के लिए गया था । हमारे साथ में पंजाब का एक डेलिगेशन भी था और राजस्थान का भी एक डेलिगेशन था । सभापति महोदय, जब नहर बंद होती है, नहर का निम्नीकरण होता है साल में एक बार नहर बंद करनी पड़ती है, 21 दिन हम लोग बंद ही रहते हैं । जब दोबारा पानी उसमें छोड़ते हैं तो उसमें जितने भी जानवर पहली बार जो पानी पीता है, चाहे वह चिड़िया हो, चाहे वह कौआ हो, जो भी जानवर पानी पीता है या चाहे वह मछली हो, सारी की सारी मर जाती हैं । पहली बार इस नहर में आने पर जो पानी पीता है, इतना गंदा हाल उस नहर का है, जिसका हम लोग पानी पीते हैं ।

सभापति महोदय, मेरे यहाँ पर एक तपोवन ब्लड बैंक है । उन्होंने एक बस बनाई है । एक करोड़ रुपये लगा था । वह बस हर गाँव में जाती है और कैंसर के पेशेंट को चैक करती है, उसकी रिपोर्ट उसके मोबाइल पर भेजती है । हम लोग गाँव में पहली बार उसको लेकर गए । उस गाँव का नाम मैं रिकार्ड नहीं कराना चाहूँगा, लेकिन उस गाँव में हमने चैक किया कि 40 पेशेंट्स एक ही गाँव में, 500 की आबादी का गाँव है और 40 पेशेंट्स कैंसर के निकले और जिनको पता नहीं था कि उसे कैंसर है । जब मैंने उनको बताया कि आपको कैंसर है तो आधे तो वहीं लोट-पोट हो गए । इतना भयानक हाल है । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं । एक तरफ तो सूखे से वह लोग दिक्कतें महसूस कर रहे हैं और हम लोग गंदा पानी पीने से महसूस कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि पंजाब में जो गंदे पानी की 383 फैक्टरियाँ हैं, एक साल पहले एक फैक्टरी का बॉइलर फटा था जिसमें राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ । उस फैक्टरी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा था । फैक्टरी का नाम मेरे दिमाग में नहीं है, उसका नाम मैं भूल गया । 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा और उस फैक्टरी ने आज तक जमा नहीं करवाया । फैक्टरी वापस चालू हो गई । इन सारी की सारी बातों को देखना होगा । हम सब लोग ज़िम्मेवार लोग हैं । इस पवित्र जगह पर आकर हम लोग इस देश के लिए बात करते हैं । आने वाली पीढ़ियों के लिए चर्चा करते हैं । मैं आपके

माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी 383 जो गंदे पानी की फैक्टरियाँ लगी हैं उनको तुरंत बंद करने का काम करें। पंजाब सरकार को निर्देशित करें या फिर पंजाब सरकार से और राजस्थान सरकार से डीपीआर मंगा कर, जैसे तो हम लोग भी बात करेंगे, लेकिन केन्द्र द्वारा सरकार डीपीआर मंगा कर उसमें काम किया जाए ताकि हम लोग बच सकें।

महोदय, मैं बहुत लंबी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है। एक मुद्दा तो यह है और दूसरा मुद्दा है कि आज भी राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को नहीं मिल रहा है। राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को मिले, इसके लिए माननीय मंत्री जी और सरकार व्यवस्था करेगी।

माननीय मंत्री जी, जो मैंने बात रखी है, मैं आशा करता हूँ कि आप अपना जवाब देते समय उस संबंध में कुछ कहेंगे।

महोदय, मैं आपके इशारे को समझ रहा हूँ। आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद): महोदय, आपने मुझे सदन के पहले दिन ही बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको साधुवाद करता हूँ।

महोदय, पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी द्वारा संकल्प-पत्र के माध्यम से जो विषय सदन को बताया गया, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सही मायने में देखा जाए तो इस समय देश के अंदर जिस तरह से वाटर लेवल गिर रहा है, जब तक हम लोग नदियों को आपस में नहीं जोड़ेंगे, तब तक उसमें सुधार नहीं होगा। केवल नदियों को जोड़ने से ही काम नहीं चलेगा। मैं देखता हूँ कि गाँव के ही ज्यादातर

लोग यहाँ सांसद चुनकर आए हैं। वे इस समय शहर में रह जरूर रहे होंगे, लेकिन वे गाँव के हैं। जब तक गाँव का पानी गाँव में नहीं रूकेगा, तालाब का पानी तालाब में नहीं रूकेगा, नहर का पानी नहर में नहीं रूकेगा और जब तक हम नदियों को आपस में नहीं जोड़ेंगे, हमें नहीं लगता कि तब तक हमारा वाटर लेवल ऊपर आएगा। आज से 100-200 साल पुरानी बात आप बता रहे थे कि उस समय बुन्देलखण्ड में 8 हजार तालाब थे। अकेले बुन्देलखण्ड में 8 हजार तालाब थे। इसी तरह पहले हर स्टेट में, हर गाँव में दो-दो, तीन-तीन तालाब थे। आज हम तालाबों की स्थिति दयनीय देख रहे हैं। जिस भी गाँव में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ तालाब को गाँव वालों ने डस्टबिन बना रखा है।

महोदय, आप गाँव के तालाबों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वे डस्टबिन की तरह हो गए हैं। गाँव में यदि कोई भी सामान टूट-फूट जाता है, छलनी टूट जाती है, जूते-जुराब खराब हो जाते हैं, घर का जो भी कचरा होता है, गाँव वाले उसे तालाब में डाल देते हैं। उस तालाब का पानी पीने लायक होता ही नहीं है। उस पानी में जो मच्छर पैदा होते हैं, अगर वे कहीं किसी के शरीर पर जाकर बैठ जाते हैं, तो उससे शरीर पर फलके पड़ जाते हैं और उससे तरह-तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। कभी हमारे गाँव के जो तालाब होते थे, गाँव के जानवर उनका पानी पीते थे और यहाँ तक कि गाँव के कुछ लोग उसमें अपने कपड़े आदि भी धो लेते थे। आज स्थिति यह हो गई है कि तालाब के पानी को कोई छूना नहीं चाहता है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि हिन्दुस्तान में जो भी तालाब हैं, मैंने तो अपने यहाँ कई बार जिलाधिकारी से कहा है कि मनरेगा के अन्तर्गत तालाब का सुन्दरीकरण कराया जाए। हम लोग तालाब को किसी भी सूरत में डस्टबिन न बनने दें, क्योंकि आज गाँव का कोई भी कचरा होता है, गाँव में किसी की कोई भी चीज टूट जाती है तो वह उसे तालाब में डाल देते हैं। पूरे देश को लोगों को हमें इस बारे में जागरूक करना चाहिए। हमें इस संबंध में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि जहाँ भी हमारे जल स्रोत हैं, चाहे वे झीलें हैं, चाहे तालाब हैं, चाहे नहरें हैं, उनका उपयोग हम डस्टबिन की तरह न करें। जो हमारी पूर्व में सरकारें रही हैं, उनकी कहीं न कहीं इस तरह की उदासीनता रही और लोगों में

उस तरह से जागरूकता पैदा नहीं की गई, जिसकी वजह से आज हिन्दुस्तान की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। जब हम लोग गाँव में जाते हैं, तो हमें यह लगता है कि कोई कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालेगा, हैंडपम्प से पानी निकालकर हमें पिलाने के लिए लाएगा। हम गाँव में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी वे हमारे पीने के लिए पानी की बोतल लाते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद शहर तीन-तीन नदियों के मध्य में स्थिति है। गंगा नदी हमारे पूरे लोक सभा क्षेत्र में बह रही है। हमारे यहाँ रामगंगा नदी भी बह रही है। हमारे यहाँ काली नदी भी बह रही है। हम लोग जिस भी गाँव में जाते हैं, तो वे हमें घर का पानी नहीं पिलाते हैं। हम लोगों के स्वागत में वे वैसे पानी की व्यवस्था करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि जो पानी आप लोग पीते हो, वही पानी हमें पिलाइए। हमें इसका चिंतन करना पड़ेगा। हम लोगों के यहां कहा जाता था कि जल से पतला क्या है? गाँव में कोई भी आदमी कभी पानी मांगने आता था या नलकूप पर भरने आता था या कुएँ पर भरने आता था तो उसके लिए कोई मना नहीं करता था। पर, आज स्थिति यह हो गयी है कि लोग अन्न जैसी चीजें तो दे देते हैं, पर पानी के लिए कहते हैं कि पानी नहीं है। इसके लिए हम सबका चिंतन होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि मैं गाँवों में जिस तरह से देख रहा हूँ, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में, विशेषकर हमारा जो बेल्ट है, जैसे फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, मैनपुरी है, इटावा है, औरैया है, एटा है, बदायूँ है, इन क्षेत्रों में मक्का 21 जून के बाद बोया जाता था। उस समय मॉनसून आ जाता था और 21 जून के बाद मक्का बोया जाता था और मूंगफली की फसल होती थी। अब स्थिति यह है कि जनवरी-फरवरी में ही मक्के की फसल बो दी जाती है जो इस समय मक्का तैयार हो जाती है। मक्के का उत्पादन तो अच्छा है, लेकिन उसमें पानी तो लगता ही है। इस समय भूमिगत जल का स्तर 15-20 फुट नीचे चला जाता है। हमारे यहां हैंडपंप पानी देना बंद कर देते हैं। किसानों को थोड़े-से लाभ की वजह से, मक्का या मूंगफली का उत्पादन होने के थोड़े लाभ में हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, हमें इसकी कल्पना नहीं है। हम लोग भूमिगत जल का कितना पानी निकाल रहे हैं और हम उस कीमती जल को फसलों में लगा-लगा कर बर्बाद कर

रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो फसल जिस सीजन की है, जैसे मक्का जब बोनी चाहिए, उसी समय मक्का बोयी जानी चाहिए। अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ऐसा बुंदेलखण्ड केवल एक ही नहीं होगा, बल्कि हिन्दुस्तान में हर गांव, हर जनपद एक तरह से बुंदेलखण्ड के रूप में तब्दील हो जाएगा। बुंदेलखण्ड की आज जो स्थिति है, आज से 100 साल पहले ऐसी नहीं रही होगी। इसलिए हम सबका इस पर चिंतन होना चाहिए। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो भी फसलें हो रही हैं, उनका जब समय हो, तब ही बोना चाहिए। जिस समय मक्के की फसल का सीजन हो, जैसे वह बरसात में होता है, वह उस समय ही बोया जाना चाहिए। उसके ऐसे बीज तैयार किए जाएं, जिससे कम पानी में भी उस फसल की पैदावार ठीक से हो सके।

अन्ना पशु की जो बात कही गयी है तो हमें एक बार वर्ष 2016 में बुंदेलखण्ड के दो-तीन विधान सभाओं में भेजा गया। मैं जिधर से भी निकलता था, हाईवे पर पूरे के पूरे अन्ना जानवर बैठे हुए थे। जिस खेत की तरफ देखता था, उस खेत की तरफ अन्ना जानवर घूम रहे थे। जानवरों के खाने के लिए कुछ नहीं था। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे यहां फर्रुखाबाद में भी ऐसी स्थिति है। हम जिस गांव में जाते हैं और जब लोगों से पूछते हैं कि बिजली आ रही है तो वे कहते हैं कि हाँ, बढ़िया आ रही है। हमने पूछा कि क्या आपको और कुछ चीजों में प्रॉब्लम है, जैसे शासन-प्रशासन, कानून-व्यवस्था में, तो वे कहते हैं कि सब ठीक है। मैं पूछता हूं कि फिर प्रॉब्लम क्या है, तो वे कहते हैं कि प्रॉब्लम एक ही है कि ये जो गाँव हैं, इन गाँवों की व्यवस्था कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे योगी जी की सरकार में मुख्य मंत्री माननीय योगी जी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन यह समस्या भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हम लोगों को इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा। अगर किसी ने चार-पाँच बीघे पर गेहूं की फसल लगा दी और रात-रात भर उसकी रखवाली करके गेहूं को बचाया, पर अगर एक दिन उसकी आंख लग गयी तो उसका पूरा का पूरा गेहूं चला गया। इस तरह से किसान बेचारा अन्ना जानवरों से बहुत परेशान है। इसके लिए केवल राज्य सरकार अकेले नहीं, बल्कि भारत सरकार भी इसके लिए सहयोग दे या यहां से कोई ऐसी

व्यवस्था बनाई जाए। जैसे वहां लोग जानवरों का दूध निकाल कर या जो जानवर दूध देना बंद कर देते हैं, उन जानवरों को छोड़ देते हैं। ऐसे जानवर झुंड के रूप में उन खेतों में चले जाते हैं, जहां उन्हें हरियाली मिलती है और वे किसानों की पूरी फसल तबाह कर देते हैं। ऐसे किसान या लोग, जो अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, इन्हें भी कानून के दायरे में लाना चाहिए कि अगर कोई किसान ऐसे जानवरों को छोड़ेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई आदमी किसी जानवर का दूध पीता है या दूध निकालता है तो उस जानवर को उसे बांध कर खिलाना भी चाहिए और यदि दूध नहीं देता है, तब भी उसे खिलाना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए। इस तरह से जरूर एक नियम होना चाहिए। यहां से हम लोग इस बार भारत सरकार से मांग रख रहे हैं। आज इस संकल्प के माध्यम से बात चर्चा में आयी है। हम लोग यह बात जरूर कहना चाहते हैं कि अन्ना पशुओं की समस्या का समाधान होना चाहिए।

दूसरा, यदि पानी की समस्या इसी तरह निरंतर बनी रहेगी तो जिस तरह से हमारे माननीय सदस्य श्री पुष्पेन्द्र चन्देल जी जो कह रहे थे, इस तरह से वाकई जिस जनपद में पानी की किल्लत होगी, उस जनपद के नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगार होकर दिल्ली तथा मुम्बई जैसे बड़े शहरों की तरफ पलायन करेंगे। उनको लगता है कि जब वे बड़े शहरों में जाएंगे तो रोजगार मिल जाएगा। अपने जनपद में वे देखते हैं कि उनके खेत में कोई भी फसल पैदा नहीं हो रही है, वैसी स्थिति में वे बड़े शहरों में जाकर चार हजार रुपये, पांच हजार रुपये या दस हजार रुपये की मज़दूरी करना पसंद करेंगे। वे अपने यहां दस हजार रुपये में मज़दूरी करना पसंद नहीं करते हैं। वे समझते हैं कि बड़े शहर में मज़दूरी करेंगे तो उनको कोई नहीं देखेगा। गांव में उनको लगता है कि उनके पास जमीन है, 100 बीघा जमीन है, 25 बीघा जमीन है। लेकिन वे 25 बीघे जमीन में कुछ पैदा नहीं कर पा रहे हैं। कहने के लिए तो वे गांव के जमींदार हैं, लेकिन वे गांव में काम न करके बड़े शहरों में जा कर काम कर लेंगे, किसी अन्य महानगर में जा कर काम कर लेंगे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हम सभी का कर्तव्य बनता है, पूरे सदन का

कर्तव्य बनता है और आपके माध्यम से सरकार से भी अनुरोध है कि हम सब लोगों को इस पर तुरंत ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे हमारी नदियां आपस में जोड़ी जा सकें। अगर नदियां आपस में नहीं जोड़ी जाएंगी तो पानी की समस्या हमेशा बनी रहेगी। मैं देखता हूं कि कभी-कभी हमारे यहां गंगा जी में बाढ़ आ जाती है। गंगा जी में इतना पानी है जिससे बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ के पानी से लोगों की फसल खराब हो जाती है। बाढ़ से गांव के गांव कट जाते हैं। कभी-कभी मैं देखता हूं कि रामगंगा नदी सूखी पड़ी रहती है या काली नदी सूखी पड़ी रहती है। यदि नदियां आपसे में लिंक हो जाएंगी तो ये बराबर में रहेंगी। इससे हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा। इससे बाढ़ की समस्या को भी रुकावट मिलेगी। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जो सपना देखा था, हमें लगता है कि इस समय वह वक्त है। अब सही वक्त है और इस पर काम होना चाहिए। नदियों को बिना जोड़े हम अपने मीठे पानी के लेवल को नहीं बचा पाएंगे। मीठा पानी ही आगे जाकर समुद्र में गिरता है और वह खारा हो जाता है। इसलिए मीठे पानी को बचाना हमारी सरकार तथा हम सबकी जिम्मेदारी बनती है।

हमारे चन्देल साहब ने जो संकल्प लाया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और इसका पूरा समर्थन करता हूं।

जय हिन्द – जय भारत ।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापति महोदय, आज मुझे 17वीं लोक सभा में जीरो ऑवर में बोलने का मौका मिला था। आपने भी मुझे इस संकल्प पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

आदरणीय सांसद श्री चन्देल जी जो बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं । इनके द्वारा जो संकल्प लाया गया है, इसमें इन्होंने केन नदी को बेतवा से जोड़ने की बात कही है । जल संकट के कारण पशुओं को चारे की जो समस्या है, इस बात को लोक सभा में रखा गया है । जब तक हम बुंदेलखंड में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल नहीं देंगे तब तक वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है । विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिस समय वर्ष 1998 में पहली बार उनकी सरकार बनी थी, उन्होंने उसी समय इन नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव लाया था । उस समय काम हुआ था । वर्ष 2004 तक तेजी के साथ काम हुआ, लेकिन वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक इन नदियों को जोड़ने का जो प्रस्ताव था, वह बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया था । आज पुष्पेन्द्र चन्देल जी केन नदी को बेतवा से जोड़ने का जो प्रस्ताव लाए, वह बहुत अच्छा प्रस्ताव है । विशेष रूप से जब यह नदी जुड़ जाएगी, बेतवा में जुड़ने के बाद हमारे लिए, क्योंकि मैं भी बुंदेलखण्ड से आता हूं, यह बेतवा नदी हमारे सम्पूर्ण बुंदेलखण्ड से होती हुई आगे जाकर पुनः हमीरपुर की ओर जाती है । यह जितना एरिया असिंचित है, वह सिंचित हो जाएगा । आज हम किसानों की बात कर रहे हैं । विशेष रूप से अन्ना पशुओं से किसान बुरी तरीके से त्रस्त है । जो अन्ना पशु की समस्या है, यह आज की समस्या नहीं है । जब 2017 का चुनाव हुआ था, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बुंदेलखण्ड में, उरई क्षेत्र में गए थे, उस समय बुंदेलखण्ड के किसानों ने इस समस्या को उठाया था । क्षेत्र की उस समस्या के निदान के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने वचन भी दिया था । उन्होंने इसका निदान करने के लिए ढेर सारी योजनाएं दी हैं ।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2017 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमारे योगी जी ने अन्ना पशु के निदान के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं । उन्होंने गौशालाओं की व्यवस्थाओं के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से, हर एक ग्राम सभा में, कोई बिरली ही छोटी ग्राम सभा होगी, जिसमें इसे न बनाया गया हो, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जहां-जहां अन्ना पशु की समस्या है, 9 लाख रुपये की

गौशाला बनाने का एक प्रावधान किया है। साथ ही साथ उन्होंने जो हमारे टाउन एरियाज हैं, उनमें भी 3 लाख से लेकर 3 करोड़ 50 लाख तक की गौशालाएं बनाने के लिए पैसा दिया है और उससे काम चल रहा है। विशेष रूप से बुंदेलखण्ड में जो गौशालाएं बनाई जा रही हैं, उसका उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मॉडल ही दे दिया है। इसमें 1 करोड़ 65 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। उस 1 करोड़ 65 लाख में जहां यह गौशाला बनाई जाएगी, सबसे पहले उस गौशाला के अंदर एक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। अगर हमारी गायें वहां बीमार होती हैं, ऐसी कोई स्थिति आती है, तो उस अस्पताल में उनका इलाज कराया जा सकेगा। उसी बाउंड्री के अंदर हमारी गौशालाओं के अंदर गायों के लिए टीन शेड बनाया जा रहा है। उस टीन शेड के माध्यम से उन गायों को छाया मिल सकेगी, वे उसमें बैठ सकेंगी। हम लोग देखते हैं कि गौशालाएं बनी हुई थी, उन गौशालाओं में अकारण ही धूप और गर्मी के कारण सैकड़ों गाय मर गई थीं। इसके बाद लोगों ने यह कहना प्रारम्भ कर दिया था कि इससे तो अच्छा है कि इन गायों को छोड़ दिया जाए और इनको किसी तरह से बचाया जाए। टीन शेड का निर्माण उन गौशालाओं में कराया जा रहा है।

गांव में गौशाला के अंदर एक भूसे का स्टोर भी बनाया जाएगा, जिससे गायें भूखी न रहें, उन्हें समय पर भोजन और जल मिल सके, जिससे उनका संरक्षण किया जा सके। यहां तक उसी गौशाला के अंदर ऐसे कमरे बनाए जाएंगे, जिसमें उन गायों को देखने के लिए एक कर्मचारी रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो अन्ना पशु प्रथा है उसे समाप्त करने के लिए पूरे जोर-शोर से लगी हुई है और इसके लिए ढेर सारा पैसा दे रही है। पैसों के साथ-साथ उसकी चिंता भी कर रही है, मॉनिटरिंग भी कर रही है कि जो गौशालाएं बनाई जा रही हैं, वे शीघ्र बनाई जा सकें, जिससे हम अन्ना पशु की समस्याओं का निदान पा सकें।

महोदय, हम लोगों के सामने एक बात आती है कि अन्ना पशुओं में हमारी गाय माता है, बछड़ा है, सांड है, ये अन्ना घूमते रहते हैं। अन्ना घूमने की वजह से हमारी गाय दो किलो, तीन किलो दूध देती है, चार किलो दूध देती है, जब तक चार किलो दूध देती रहती है तब तक किसान उसे बांधे रखता है। चार किलो के

बाद जैसे ही दो किलो पर आती है उसे छोड़ देता है, उसके बाद वह अन्ना हो जाती है, अन्ना होने के बाद वह दूसरे की फसलों को नुकसान पहुंचाती है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी चिंता की है, विशेष तौर से एक कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जा रही है। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जो बछिया हैं, जो सीमेन डाला जाएगा, उससे जो नस्ल पैदा होगी, वह सिर्फ बछिया ही होगी, बछिया पैदा होने के बाद और बछड़े पैदा नहीं होंगे, धीरे-धीरे अन्ना पशुओं की समस्या का निदान हो जाएगा। इसमें समय लगेगा और समय लग भी रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार किसानों को नुकसान न हो, उनको किसी तरीके से लाभ दे सकें, ऐसी सारी योजनाएं केन्द्र और राज्य सरकार बना रही है।

सभापति महोदय, इन सारी बातों के बावजूद भी हम लोग कह सकते हैं, किसानों की सिंचाई के लिए हमारे यहां एक पसना बांध है, पसना बांध मध्य प्रदेश के भिंड की सीमा को छूता है, इटावा की सीमा से छूता है, हमारे जनपद जालौन की सीमा है। तीनों जिलों की सीमा में बसा हुआ एक पसना बांध है, जहां पांच नदियां आकर मिलती है, हम लोग वर्षों से कह रहे हैं कि वहां बांध बन जाएगा तो बुंदेलखंड के साथ-साथ हमारे जो कानपुर क्षेत्र का भाग है, जो सूखे की स्थिति को झेलता है, वर्षा न होने की वजह से पानी की परेशानी होती है, वहां अगर बांध बना दिया जाए तो निश्चित ही समस्या का निदान मिल सकता है। वहां पांच नदियां हैं, यमुना नदी है, कुंवारी नदी है, सिंध नदी है, बहुज नदी है, चमोल नदी है, इन पांच नदियों को मिलाने पर पर्याप्त जल है। उसमें बांध बनने की कई बार स्थितियां आईं।

पूर्व जल संसाधन मंत्री हमारी बहन उमा भारती जी ने उसका सर्वे भी किया था, उसे देखा था और उस पर थोड़ा बहुत काम भी किया था। हम लोग आशा करते हैं, सरकार हमारी है तो निश्चित ही उस पर बांध बनाने का काम करना चाहिए, क्योंकि आज बुंदेलखंड के किसानों की जो दयनीय स्थिति है, वह अपने क्षेत्र को छोड़ कर किसी तरीके से दिल्ली आकर बसते हैं, किसी तरीके से मजदूरी करते हैं। कोई दूसरे के यहां काम करते हैं और जीवनयापन करते हैं। जब झांसी से दिल्ली के लिए आते हैं, वहां से यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन चलती है, उस

संपर्क क्रांति में हम लोग देखते हैं कि बुंदेलखंड के लोग अपने बीबी बच्चों को साथ लेकर ट्रेन में आते हैं, निजामुद्दीन स्टेशन पर उतरते हैं, वह देखते ही बनता है। वह अपने सिर पर गठरी रखे हुए और बच्चों को हाथ में लिए हुए दिल्ली में सिर्फ रोजगार के लिए भटकते फिरते हैं। वे किसान हैं, उनके पास जमीन है, बुंदेलखंड में किसानों के पास ज्यादा जमीन है, लेकिन वहां पैदावारी कम है। बुंदेलखंड के अलावा हम लोग कहीं और जाते हैं तो देखते हैं कि किसी के पास अगर दो एकड़ जमीन है तो वह किसान खुशहाल है, लेकिन हमारे यहां किसान को दस एकड़ भी जमीन है तो वह खुशहाल नहीं है क्योंकि दस एकड़ जमीन उसके पास है, लेकिन उसमें पैदा कुछ नहीं होता है। सिंचाई का कोई साधन नहीं है इसलिए किसान पूरी तरह से तबाह रहता है। उसकी मजबूरी रहती है कि किसी तरीके से वह बाहर जाकर काम करे। विशेष रूप से किसानों की सिंचाई के लिए जो प्राइवेट ट्यूबवेल की सुविधा किसानों को दे दें तो हमारे किसान प्राइवेट ट्यूबवेल लगा कर अपने खेत को सिंचित कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। विशेष रूप से कुछ ट्यूबवेल दिए गए थे लेकिन अभी बीच विद्युत कनेक्शन में कुछ सब्सिडी थी, किसानों को विद्युत की सब्सिडी नहीं मिल पा रही है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य वर्मा जी, समय पूरा हो गया है और छह बज गए हैं, आप अगली बार कन्टीन्यू कीजिएगा। आपका वक्तव्य अभी अधूरा माना जा रहा है, उसे आप पूरा कीजिएगा।

सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 24 जून, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18. 00hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, June 23, 2019/ Ashadha 3, 1941(Saka)*

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

** Unstarred Question Nos.20, 66 and 114 were deleted due to appointment of Shri Om Birla as the Hon'ble Speaker.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT11/17/2019.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 12/17/19.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Not recorded.

* Not recorded.